

संक्षिप्त समाचार

इटावा में महिला से लूट का आरोपी मुठभेड़ में घायल

इटावा। यूपी के इटावा जिले के भरथना-बिधुना मार्ग पर पड़ियापुरा गांव के पास महिला से हुई लूट की घटना का पुलिस ने खुलासा करने का दावा किया है। रात 10 बजे चेकिंग के दौरान पुलिस और आरोपी के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस के मुताबिक, आरोपी अनुज शाक्य ने पुलिस टीम पर फायरिंग की, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में उसके बाएं पैर में घुटने के नीचे गोली लग गई। घायल आरोपी को गिरफ्तार कर सीएचसी भरथना में भर्ती कराया गया। पुलिस ने उसके कब्जे से लूट के 700 रुपये, तमंचा, कारतूस और घटना में इस्तेमाल की गई अपाचे मोटरसाइकिल बरामद की है। एसपी ग्रामीण श्रीशचंद्र ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस ने महिला से लूट की घटना में शामिल आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ इटावा, मैनपुरी, फतेहगढ़ औरैया समेत कई जिलों में 30 से अधिक मुकदमे दर्ज होने की जानकारी सामने आई है। पुलिस आरोपी के अपराधिक इतिहास और घटना से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच कर रही है।

अखिलेश और राहुल पर ओपी का तंज, कहा-अगर गड़बड़ियां हैं तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार के पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर हमला बोला। उन्होंने अभिजीत दिपके को हिरासत में लिए जाने सहित कई मामलों पर प्रतिक्रिया दी। आईएनएस से बातचीत करते हुए केंद्रीय मंत्री जी. किशन रेड्डी के बयान पर ओम प्रकाश राजभर ने कहा, वे सही कह रहे हैं। जिस तरह अखिलेश यादव दूसरों की कही बातों पर चलते रहते हैं और अपने ही बयानों पर कायम नहीं रहते, राहुल गांधी भी बिल्कुल वैसा ही करते हैं। वे गैर-जिम्मेदाराना तरीके से काम करते हैं और उनके सभी कदम देश के खिलाफ होते हैं। राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए ओम प्रकाश राजभर ने कहा, राहुल गांधी और अखिलेश यादव हमेशा संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाए हैं। वे उसी चुनाव आयोग के तहत सांसद बने, जिसकी वे अब आलोचना कर रहे हैं। अगर उनका दावा है कि गड़बड़ियां हो रही हैं और वोट चुराए जा रहे हैं।

प्रतापगढ़ में धारदार हथियार से पत्नी की हत्या, नशे में पति ने दिया वारदात को अंजाम

प्रतापगढ़। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां फतनपुर थाना इलाके के पटहटिया कला गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में महिला मंजू यादव की मौत हो गई। महिला की मौत के बाद पति अजय यादव ने ही पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस जब जांच में जुटी तो सच्चाई कुछ और ही निकली। जांच में पता चला कि मंजू को मौत के घाट उतारने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका पति अजय यादव ही है।

पंजाब के संगरूर में भीषण सड़क हादसा

कार ने मनरेगा मजदूरों को कुचला,मौके पर 9 की मौत

पंजाब/ एजेंसी

पंजाब के संगरूर जिले में रविवार की दोपहर एक बड़े मातम में बदल गई, जब रोजी-रोटी की तलाश में सड़क किनारे काम कर रहे गरीब मनरेगा मजदूरों पर एक बेकाबू कार कहर बनकर टूट पड़ी। लहरागागा-जाखल मार्ग पर अचानक हुई इस खौफनाक दुर्घटना ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। काम में जुटे मजदूरों को संभलने तक का अवसर नहीं मिला और तेज गति से आ रही कार उन्हें रौंदती हुई निकल गई। इस दर्दनाक हादसे के बाद पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है और पीड़ित परिवारों में चीख-पुकार मची हुई है। प्रत्यक्षदर्शियों और पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, यह भीषण सड़क दुर्घटना संगरूर जिले में लहरा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव अल्लोशेर और चोटियां के नजदीक हुई। वहां सड़क निर्माण और मरम्मत का कार्य चल रहा था। इसी दौरान लहरागागा-जाखल मुख्य मार्ग पर एक अनियंत्रित और अत्यधिक तेज रफ्तार कार अचानक मजदूरों के कार्यस्थल में घुस गई। टक्कर इतनी जबर्दस्त थी कि कई मजदूर हवा में उछलकर दूर जा गिरे। शुरुआती जांच में सामने आया है कि हादसे के समय घटनास्थल पर करीब 23 महिला और पुरुष मनरेगा मजदूर सड़क किनारे अपने दैनिक कार्य में जुटे हुए थे। अचानक आई तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे काम कर रहे मजदूरों के समूह को सीधे अपनी चपेट में ले लिया। तेज टक्कर और कुचले जाने के कारण घटनास्थल पर ही नौ मजदूरों ने दम तोड़ दिया। मृतकों में महिला मजदूर भी शामिल बताई जा रही हैं। हादसे में कई अन्य मजदूर भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। दुर्घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी तुरंत दलबल के साथ मौके पर पहुंचे। एंबुलेंस की सहायता से सभी घायलों को फौरन पास के सरकारी और



महाराष्ट्र के बीड में कार और बस की आमने-सामने की भीषण टक्कर,एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत

नवरात्रि के पावन माहौल के बीच तुलजापुर में दर्शन-पूजन के लिए निकला एक परिवार रास्ते में ही भीषण सड़क हादसे का शिकार हो गया। बीड जन्मद के माजलगांव-तेलगांव मार्ग पर स्थित शिंदेवाडी फाटे के पास कार और एसटी बस की यह टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। हादसे में पांच लोगों की जान जाने के बाद क्षेत्र में मातम पसर गया है। प्रत्यक्षदर्शियों और पुलिस के अनुसार, यह भयानक सड़क दुर्घटना सुबह करीब 11 बजे खामगांव-वडपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर शिंदेवाडी फाटा स्थित अविनाश दादा बसोडे के पेट्रोल पंप के सामने हुई। माजलगांव का एक परिवार कार में सवार होकर तुलजापुर तीर्थयात्रा के लिए निकला था। यात्रा के दौरान जैसे ही कार पेट्रोल पंप के पास पहुंची, सामने से अपनी लेन में सामान्य गति से आ रही एसटी बस से उसकी जोरदार टक्कर हो गई। हादसे का एक रोंगटे खड़े कर देने वाला सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जो पास ही लगे केमरे में रिकॉर्ड हो गया। वीडियो में साफदेखा जा सकता है कि हाईवे पर अन्य वाहन सामान्य रफ्तार से चल रहे थे और एसटी बस भी अपनी तय लेन में नियंत्रित गति से बढ़ रही थी। तभी अचानक सामने से आ रही कार अपना संतुलन खो बैठी और सीधे बस के अगले हिस्से में जा टकराई। फुटेज से साफहोता है कि टक्कर से पहले ही कार वालक का नियंत्रण पूरी तरह खो चुका था। शुरुआती जांच और प्रत्यक्षदर्शियों की रिपोर्ट के मुताबिक, हाईवे पर बने गहरे गड्ढे और खराब पैवमेंट के कारण कार अनियंत्रित हुई थी। गड्ढे से बचने या उसमें पहिया जाने से वाहन का संतुलन बिगड़ा और वह सीधे बस के सामने पहुंच गई। इस दर्दनाक घटना के बाद स्थानीय नागरिकों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने घटनास्थल पर पहुंचकर 'रास्ता रोको' आंदोलन शुरू कर दिया।

निजी अस्पतालों में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों की टीम उनके उपचार में जुटी हुई है। अस्पतालों में भर्ती कुछ घायलों की हालत अत्यंत नाजुक बताई जा रही है। इस घटना की खबर जैसे ही आसपास के गांवों में फैली, सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण और परजनों की भीड़ मौके पर जुट गई। अपनों को खो चुके गरीब परिवारों का रो-रोकर बुरा हाल है। स्थानीय प्रशासन की ओर से राहत और बचाव कार्य को प्राथमिकता दी जा रही है। पुलिस ने

दुर्घटनाग्रस्त कार को कब्जे में लेकर चालक के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। दुर्घटना के बाद घटनास्थल पर अपरा-तफरी का माहौल बन गया। स्थानीय लोगों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाने और मौके पर राहत व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए हैं। हादसे में घायल लोगों को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। पुलिस मृतकों और घायलों की संख्या के साथ उनकी पहचान की जानकारी जुटा रही है।

लोकतंत्र में सरकार बदलना प्रक्रिया का हिस्सा: पी चिदंबरम

नई दिल्ली। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने सरकार बदलना शब्द के इस्तेमाल का बचाव करते हुए इसे एक सामान्य लोकतांत्रिक प्रक्रिया बताया और कहा कि चुनावों के जरिए सरकार को हटाना विपक्ष का काम है। यह तब हुआ जब विपक्षी नेताओं और छात्र कार्यकर्ता ने वोट चोरी को लेकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ दिल्ली में चल रहे प्रदर्शन के बीच सरकार बदलना शब्द का इस्तेमाल किया। सीनियर एडवोकेट प्रभात भूषण ने कहा कि प्रोटेस्ट अब सरकार बदलने की लड़ाई में बदल गया है और इसे नागरिकों का लोकतांत्रिक अधिकार बताया।

ग्वालियर में बेकाबू ट्रक का कहर

शीतला माता मंदिर जा रहे 41 श्रद्धालुओं को कुचला,15 की मौत

■ 26 घायल; 8 पुलिस कर्मी-अफसर सस्पेंड

ग्वालियर/ एजेंसी

ग्वालियर में देर रात शीतला माता मंदिर जा रहे श्रद्धालुओं के साथ भीषण हादसा हो गया। चीनौर रोड पर ढलान से उतरते समय धान से भरा तेज रफ्तार ट्रक बेकाबू हो गया। ट्रक ने सड़क किनारे दर्शन के लिए लाइन में लगे 41 श्रद्धालुओं को कुचल दिया। हादसे में 15 लोगों की मौत हो गई, जबकि दो पुलिसकर्मीयों समेत 26 लोग घायल हो गए। हादसा रात करीब 1:30 बजे हुआ। ट्रक पुलिस चेकपोस्ट तोड़ते हुए मंदिर के गेट और बाहरी दीवार से टकरा गया। टक्कर से दीवार ढह गई और कई लोग मलबे में दब गए। घायलों को जयारोग्य



अस्पताल में भर्ती कराया गया है। परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। पुलिस के मुताबिक, ड्राइवर गूगल मैप की मदद से ट्रक चला रहा था। उसने ब्रेक फेल होने की बात कही है। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर और मालिक को गिरफ्तार कर लिया है। हादसे के बाद सरकार ने सिटी

एसपी को हटा दिया और चार टीआई समेत आठ अफसरों व पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया। हादसा शनिवार और रविवार की दरमियानी रात करीब 1:30 बजे हुआ। चीनौर की ओर से शीतला माता मंदिर आ रहा धान से भरा ट्रक ड्राइवर और मालिक को गिरफ्तार खो बैठा। ट्रक पुलिस बैरिकेड तोड़ते हुए श्रद्धालुओं की

भीड़ में जा घुसा और मंदिर के प्रवेश द्वार व बाहरी दीवार से टकरा गया। टक्कर के बाद दीवार का हिस्सा ढह गया और कुछ लोग मलबे में दब गए। हादसे के बाद मौके पर अपरा-तफरी मच गई। पुलिस और प्रशासन की टीमों ने राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। घायलों को एंबुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार जारी है। कुछ घायलों की हालत गंभीर बताई गई है। नवरात्रि के दौरान शीतला माता मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में मंदिर की ओर जाने वाले पहाड़ी मार्ग पर भारी वाहनों की आवाजाही रोकने के लिए बैरिकेड और पुलिस चेक-पॉइंट लगाए गए थे। इसके बावजूद ट्रक प्रतिबंधित मार्ग पर कैसे पहुंचा, इसकी जांच की जा रही है। ट्रक की तकनीकी जांच के जरिए हादसे के कारणों का पता लगाने की भी कोशिश की जा रही है।

सीएम सुवेंदु अधिकारी ने किया मुआवजे का ऐलान

मृतकों के परिजनों को 25 लाख और सरकारी नौकरी,घायलों को 5 लाख

कोलकाता। एजेंसी

पश्चिम बंगाल के कोलकाता स्थित चोरबागान सार्वजनिक दुर्गा पूजा पंडाल में भगदड़ की घटना के बाद राज्य सरकार ने मृतकों के परिजनों और घायलों के लिए मुआवजे का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने बताया कि हादसे में 19 लोगों की मौत हुई है, जबकि 25 लोग घायल हुए हैं। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 25-25 लाख रुपये की आर्थिक सहायता और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री के मुताबिक, घायलों को 5-5 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। उनके इलाज का पूरा खर्च



भी राज्य सरकार उठाएगी। अधिकारी ने कहा कि सरकार प्रभावित परिवारों के साथ खड़ी है और राहत एवं सहायता के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है। सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि वह कलकत्ता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर घटना की जांच के लिए तथ्य-जांच समिति गठित करने का अनुरोध

करेंगे। उनके अनुसार, प्रस्तावित समिति में स्क्वअर और फोरेंसिक टीमों शामिल होंगी, ताकि हादसे से जुड़े तथ्यों और परिस्थितियों की जांच की जा सके। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने घटना के संबंध में मुख्य सचिव से रिपोर्ट मांगी थी, जिसे सरकार ने सौंप दिया है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार इस मामले में मिलकर काम कर रही हैं। अधिकारी ने हादसे को राजनीतिक रंग देने की कोशिशों पर भी आपत्ति जताई। उन्होंने पिछली सरकार के कार्यकाल और वर्ष 2025 में हुई अन्य घटनाओं का जिक्र करते हुए विपक्ष पर निशाना साधा।

ड्राइवर के घायल होने की खबर

टाइगर श्रॉफ पर 3 बाइक सवार ने की फायरिंग.....

नई दिल्ली। बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग हुई है। इस घटना में एक फैन और एक्टर के ड्राइवर के घायल होने की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि बाइक पर सवार लोगों ने उन्हें निशाना बनाते हुए फायरिंग की थी। इस घटना में उनके ड्राइवर के घायल होने की खबर सामने आई है। साथ ही घटनास्थल पर मौजूद एक फैन के भी घायल होने की खबर है। रिपोर्ट के मुताबिक, टाइगर श्रॉफ फुटबॉल खेलने के लिए जुहू के पुष्पा पार्क इलाके के पास मौजूद थे। तभी एक बाइक पर सवाल



तीन लोग वहां पहुंचे और एक्टर की गाड़ी पर फायरिंग शुरू कर दी। इस फायरिंग में घटनास्थल पर मौजूद एक ऑटो वाले को भी गोली लगने की खबर सामने आई है। मौके पर एंबुलेंस पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचा गया

ईरान होर्मुज खोलने को तैयार

डोनाल्ड ट्रंप बोले- ईरान के साथ युद्ध बहुत जल्द खत्म होगा.....

नई दिल्ली/ एजेंसी

ईरान और अमेरिका के बीच आठ महीने से जारी युद्ध को समाप्त करने के लिए बातचीत की संभावनाएं बनी हुई हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने रविवार को कहा कि होर्मुज जलडमरूमध्य को सात दिनों के भीतर दोबारा खोलने का प्रस्ताव अब भी बरकरार है। हालांकि, उन्होंने अमेरिका पर समझौते के लिए ईमानदारी नहीं दिखाने का आरोप लगाया। इराक की राजधानी बगदाद में इस्लामिक सहयोग संगठन की बैठक में



शामिल होने पहुंचे अराघची ने ईरानी मीडिया से कहा कि तेहरान अमेरिका के जवाब की समीक्षा कर रहा है। उन्होंने कहा कि यदि अमेरिका ईरान को शर्तें स्वीकार कर लेता है, तो छह दिनों के भीतर जलडमरूमध्य खोला जा

सकता है और अगले दिन बातचीत फिर शुरू हो सकती है। ईरान की प्रमुख मांगों में उसके बंदरगाहों पर अमेरिकी नाकेबंदी हटाना, ईरानी तेल निर्यात पर लगे अमेरिकी प्रतिबंध समाप्त करना और क्षेत्र के सभी मोर्चों पर युद्ध रोकना शामिल है। बातचीत में सबसे बड़ा मतभेद ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर है। अमेरिका चाहता है कि वार्ता की शुरुआत में ही परमाणु कार्यक्रम पर चर्चा हो, जबकि ईरान पहले होर्मुज जलडमरूमध्य को खोलने और वहां सुरक्षा बहाल करने पर जोर दे रहा है।

कोलकाता दुर्गा पूजा पंडाल हादसा: अब तक 19 की मौत एसआईटी जांच का ऐलान, घायलों से मिले अभित शाह

कोलकाता के चोरबागान सार्वजनिक दुर्गा पूजा पंडाल में शनिवार रात मची भगदड़ में 19 लोगों की मौत हो गई, जबकि 25 लोग घायल हुए हैं। घायलों का शहर के तीन अस्पतालों में इलाज चल रहा है। इनमें से पांच मरीज आईसीयू में भर्ती हैं और एक की हालत गंभीर बनी हुई है। रविवार सुबह केंद्रीय गृह मंत्री अभित शाह ने अयोली अस्पताल पहुंचकर घायलों से मुलाकात की। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने बताया कि अधिकारियों की शुरुआती रिपोर्ट के अनुसार, पूजा आयोजकों की ओर से लाउडस्पीकर पर की गई एक घोषणा के बाद मौके पर अपरा-तफरी मची। हालांकि, घोषणा में क्या कहा गया था, यह अभी स्पष्ट नहीं है। अधिकारी के मुताबिक, दो पीड़ितों के परिजनों ने यह भी दावा किया कि पंडाल के पास निजी सुरक्षा गार्ड की सीटी बजने से प्रवेश का इंतजार कर रही भीड़ में भगदड़ मच गई। इन दावों की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी। पुलिस ने मामले में गैर-इरादतन हत्या का केस दर्ज कर पूजा कमेटी के सचिव और उपध्यक्ष समेत सात लोगों को गिरफ्तार किया है। ये सभी उन 14 लोगों में शामिल हैं, जिन्हें शनिवार रात हिरासत में लिया गया था। गिरफ्तार लोगों में पंडाल के बांस के ढांचे के निर्माण और भीड़ प्रबंधन की जिम्मेदारी संभालने वाले लोग भी शामिल हैं। हादसे के बाद पंडाल की सुरक्षा व्यवस्था और भीड़ प्रबंधन पर सवाल उठ रहे हैं।



बस्तर दशहरा : सरगीपाल में विधि-विधान से संपन्न हुई ऐतिहासिक ‘बेल पूजा’

गाजे-बाजे के साथ दंतेश्वरी मंदिर लाया गया शिव-शक्ति का प्रतीक ‘युग्म बेल’

भुजबल बघेल
बकावंड, जनता के गोट 18 अक्टूबर 2026/ विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक बस्तर दशहरा पर्व की अनूठी परंपरा के तहत रविवार को सरगीपाल में पारंपरिक ‘बेल पूजा’ का विशेष विधान पूर्ण श्रद्धा, उल्लास और वैदिक विधि-विधान के साथ संपन्न हुआ। शहर से कुछ दूरी पर स्थित ग्राम सरगीपाल के प्राचीन बेल वृक्ष के समक्ष सैकड़ों ग्रामीणों और श्रद्धालुओं की उपस्थिति में यह सदियों पुरानी रस्म निभाई गई। इस रस्म का मुख्य केंद्र वृक्ष पर



प्राकृतिक रूप से एक साथ जुड़े ‘युग्म बेल’ (जोड़े में लगे फल) रहे, जिन्हें लोकमान्यता में देवाधिदेव महादेव और आदिशक्ति

मां पार्वती का साक्षात स्वरूप माना जाता है। एक दिन पूर्व ससम्मान निमंत्रण देकर लाल वस्त्र से आच्छादित किए गए इन फलों का



रविवार सुबह 11 बजे पारंपरिक अनुष्ठान शुरू हुआ। पूजा के दौरान

गांव में वैवाहिक उत्सव जैसा मांगलिक माहौल देखने को मिला,



जहां ग्रामीण महिलाओं ने पारंपरिक लोकगीतों के बीच हल्दी लगाकर उत्सव मनाया। इस अवसर पर बस्तर राजपरिवार के सदस्य एवं

माटी पुजारी श्री कमलचंद भंजदेव ने उपस्थित रहकर सभी परंपराओं का विधिवत निर्वहन किया। इस अवसर पर बस्तर सांसद एवं बस्तर

दशहरा समिति के अध्यक्ष श्री महेश कश्यप भी उपस्थित थे। धार्मिक अनुष्ठान पूर्ण होने के उपरांत पेड़ से युग्म बेल को सावधानीपूर्वक तोड़कर भव्य शोभायात्रा निकाली गई। पारंपरिक वाद्ययंत्रों और गाजे-बाजे की थाप पर निकली इस शोभायात्रा के जरिए पवित्र बेल को जगदलपुर स्थित प्रसिद्ध मां दंतेश्वरी मंदिर लाया गया, जहां इसे विधिपूर्वक स्थापित किया गया। सैकड़ों वर्ष पूर्व राजा को मिले दिव्य स्वप्न और शक्ति के आभास से शुरू हुई यह परंपरा आज भी बस्तर की सांस्कृतिक गरिमा और अटूट लोक-आस्था के साथ जीवंत रूप से निभाई जा रही है।

इंद्रावती की बाढ़ ने उजाड़े ग्रामीणों के आशियाने, मुआवजे और आवास की मांग –नीलाम्बर भट्टे

बकावंड और बस्तर विकासखंड के कई गांव प्रभावित, घरों का सामान, अनाज, मवेशी और फसलें बर्बाद

ओमप्रकाश रजक/जनता के गोट

जगदलपुर। इंद्रावती नदी में आई बाढ़ ने बस्तर जिले के नदी तटीय इलाकों में भारी तबाही मचाई है। बाढ़ के पानी से बकावंड और बस्तर विकासखंड के कई गांवों में जनजीवन प्रभावित हुआ है। अनेक घरों को नुकसान पहुंचा है, वहीं मवेशियों और फसलों की क्षति से ग्रामीणों के सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया है।

बाढ़ प्रभावित परिवारों की स्थिति का जायजा लेने बस्तर अधिकार मुक्ति मोर्चा एवं जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) के नेता नीलाम्बर भट्टे, लखी बघेल और वनमाली बकावंड विकासखंड के ग्राम चित्तालूर, धोबीगुड़ा, बालपुटी, बेलगांव, कोहकापाल सहित आसपास के गांवों में पहुंचे। उन्होंने पीड़ित ग्रामीणों से मुलाकात कर बाढ़ से हुए नुकसान और उनकी समस्याओं की जानकारी ली। ग्रामीणों ने बताया कि अचानक बाढ़ का पानी घरों में घुसने से धरेलू सामान, अनाज और बर्तन बह गए। कई परिवारों के मकानों की भारी नुकसान पहुंचा है। मवेशियों और



फसलों की क्षति ने ग्रामीणों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। प्रभावित परिवारों के सामने अब भोजन और सुरक्षित आवास की गंभीर समस्या है। इस दौरान नीलाम्बर भट्टे ने शासन-प्रशासन से मांग की कि बाढ़ से प्रभावित सभी परिवारों का निष्पक्ष सर्वेक्षण करार वास्तविक नुकसान का आकलन किया जाए।

जिन परिवारों के मकान क्षतिग्रस्त या पूरी तरह ध्वस्त हो गए हैं, उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्राथमिकता से आवास उपलब्ध कराया जाए। साथ ही मुख्यमंत्री राहत कोष से उचित मुआवजा देकर पीड़ितों को राहत पहुंचाई जाए, ताकि वे फिर से अपना जीवन व्यवस्थित कर सकें।

विधायक विक्रम मंडावी ने कौंगूपल्ली और मेटुपल्ली में महिलाओं से की भेंट-मुलाकात

बतकम्मा पर्व पर माताओं-बहनों को दी बधाई, सुख-समृद्धि की कामना की

ओमप्रकाश रजक/जनता के गोट

जगदलपुर। बीजापुर विधायक विक्रम मंडावी ने ग्राम कौंगूपल्ली एवं मेटुपल्ली पहुंचकर बतकम्मा पर्व के अवसर पर माताओं और बहनों से भेंट-मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने महिलाओं को बतकम्मा पर्व की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए सभी के सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना की।

विधायक विक्रम मंडावी की इस भेंट-मुलाकात के दौरान स्थानीय महिलाओं से आत्मीय संवाद हुआ। उन्होंने पर्व की शुभकामनाएं देते हुए क्षेत्र की



माताओं-बहनों के साथ सामाजिक और सांस्कृतिक परंपराओं के महत्व पर जुड़ाव प्रदर्शित किया। बतकम्मा पर्व महिलाओं की आस्था, प्रकृति के प्रति सम्मान और समृद्धि उत्सव की भावना से जुड़ा हुआ है। ऐसे पर्व समाज में आपसी भाईचारे, एकता और सांस्कृतिक विरासत को मजबूत बनाने में

महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बस्तर संभाग के आदिवासी अंचलों में स्थानीय पर्व और परंपराएं जनजीवन का अभिन्न हिस्सा हैं इन आयोजनों के माध्यम से लोग अपनी संस्कृति और परंपराओं को जीवंत रखते हैं तथा नई पीढ़ी को अपनी सांस्कृतिक विरासत से परिचित कराते हैं

विधायक विक्रम मंडावी की कौंगूपल्ली और मेटुपल्ली में हुई इस मुलाकात को क्षेत्र की महिलाओं के साथ संवाद और पर्व की खुशियां साझा करने के अवसर के रूप में देखा गया उन्होंने सभी माताओं-बहनों के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहने की मंगलकामना की।

एनएसएस की गतिविधियों को प्रभावी बनाने पर मंथन, जिला संगठकों एवं कार्यक्रम अधिकारियों की कार्यशाला आयोजित

महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय में वित्तीय पारदर्शिता, ऑनलाइन पंजीयन और समाज सेवा पर दिया गया जोर

ओमप्रकाश रजक/ जनता के गोट

जगदलपुर। शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर के एमबीए संभाग में राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) के जिला संगठकों एवं कार्यक्रम अधिकारियों की एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य समाज सेवा और राष्ट्र निर्माण से जुड़े कार्यों को नई गति प्रदान करना तथा एनएसएस की गतिविधियों को अधिक प्रभावी बनाना रहा।

कार्यक्रम की अध्यक्षता विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. डॉ. मनोज श्रीवास्तव ने की। छत्तीसगढ़ शासन की राज्य एनएसएस अधिकारी डॉ. नीता बाजपेई विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं। वहीं, भारत सरकार के उप कार्यक्रम सलाहकार एवं क्षेत्रीय निदेशक अशोक कुमार श्रोती ने मुख्य मार्गदर्शक के रूप में



सहभागिता की। कार्यशाला में एनएसएस गतिविधियों के सुचारु संचालन, वित्तीय प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और ऑनलाइन कार्यों की जानकारी दी गई। नुतेश कुमार वर्मा ने सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के माध्यम से राशि के आहरण एवं निकासी तथा तकनीकी समस्याओं के समाधान की जानकारी दी। एनएसएस के तकनीकी सहायक एवं कार्यक्रम अधिकारी सचेंद्र साहू ने सीजी एनएसएस पोर्टल पर नियमित गतिविधियों और विशेष शिविरों के पंजीयन एवं प्रतिवेदन अपलोड

करने की प्रक्रिया समझाई। एनएसएस कार्यक्रम समन्वयक डॉ. संजीवन कुमार भूआर्य ने निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप गतिविधियों का संचालन करने पर जोर दिया। डॉ. नीता बाजपेई ने सेवा, अनुशासन, सामाजिक जागरूकता और जनभागीदारी के माध्यम से एनएसएस को मजबूत बनाने की बात कही। कार्यशाला में बस्तर, कोंडागांव, कांकेर और दंतवाड़ा सहित विभिन्न जिलों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस दौरान अनीश कश्यप, विशाल, निकिता एवं समूह ने सांस्कृतिक प्रस्तुति दी।

बाढ़ प्रभावित किसानों को 50 हजार रुपये प्रति एकड़ मुआवजा देने की मांग, कृषि ऋण माफ़ी की उठाई आवाज छोटे देवड़ा के सरपंच संतोष कुमार कश्यप ने प्रभावित गांवों का किया दौरा, फसल बर्बादी और मकानों को हुए नुकसान का सर्वे कर तत्काल राहत देने की मांग

बकावंड जनता के गोट।

विकासखंड बकावंड के अंतर्गत ग्राम पंचायत बेड़ा उमरगांव के आश्रित गांव मेटावड़ा, तामाकोनी, धोबीगुड़ा, मालगांव, बेलगांव और गुमडेल में बाढ़ से हुए भारी नुकसान का जायजा लेने ग्राम पंचायत छोटे देवड़ा के सरपंच संतोष कुमार कश्यप ने 18 अक्टूबर को प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने किसानों की बर्बाद फसलों, क्षतिग्रस्त मकानों और ग्रामीणों की समस्याओं का जायजा लेते हुए शासन-प्रशासन से प्रति एकड़ 50 हजार रुपये मुआवजा, कृषि ऋण माफ़ी और प्रभावित परिवारों को तत्काल राहत देने की मांग की।

खेतों में रेत और पानी जमा, फसलें बर्बाद- सरपंच के अनुसार, बाढ़ के कारण धान, मक्का और सब्जियों की खड़ी फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। कई खेतों में तीन से चार फीट तक पानी और रेत जमा होने से किसानों के सामने आजीविका का संकट खड़ा हो गया है। खेतों में रेत भर जाने से आगामी फसल की तैयारी करना भी मुश्किल हो सकता है।



कच्चे मकान क्षतिग्रस्त, धरेलू सामान को नुकसान- बाढ़ से कई गरीब परिवारों के कच्चे मकानों को नुकसान पहुंचा है। घरों में रखा अनाज, कपड़े, बर्तन और

अन्य जरूरी सामान भी प्रभावित हुआ है। ऐसे परिवारों के सामने रहने और भोजन की व्यवस्था करने की चुनौती है। सरपंच ने प्रभावित परिवारों को तत्काल राहत सामग्री

उपलब्ध कराने की मांग की। कृषि ऋण की किस्तें चुकाना हुआ मुश्किल- कृषि ऋण की किस्तें चुकाना हुआ मुश्किल संतोष कुमार कश्यप ने कहा कि कई किसानों ने ट्रैक्टर, पावर टिलर, थ्रेशर और अन्य कृषि उपकरण खरीदने के लिए बैंकों तथा निजी फाइनेंस कंपनियों से लाखों रुपये का ऋण लिया है। फसल बर्बाद होने के बाद किसानों के लिए ऋण की किस्तें चुकाना मुश्किल हो गया है। उन्होंने सरकार से प्रभावित किसानों को कृषि ऋण में राहत देने, किस्तों का भुगतान कम से कम एक वर्ष के लिए स्थगित करने और ब्याज में छूट देने की मांग की।

तीन प्रमुख मांगें रखीं सरपंच संतोष कुमार कश्यप ने शासन-प्रशासन से तीन प्रमुख मांगें की हैं। पहली, बाढ़ से प्रभावित किसानों की फसलों का तत्काल सर्वे कराकर प्रति एकड़ 50 हजार रुपये मुआवजा दिया जाए। दूसरी, कृषि उपकरणों के लिए लिए गए ऋण की किस्तों में राहत देते हुए ऋण माफ़ी अथवा भुगतान स्थगन और ब्याज में छूट की व्यवस्था की जाए। तीसरी, जिन परिवारों के मकान

क्षतिग्रस्त हुए हैं, उन्हें पात्रतानुसार प्रधानमंत्री आवास योजना या अन्य आवासीय प्रभावित गांवों में भेजकर फसल, खेतों और मकानों को हुए नुकसान का तत्काल सर्वे कराने की अपील की। उन्होंने कहा कि समय पर सहायता नहीं मिलने से आर्थिक रूप से कमजोर किसान परिवारों के सामने आजीविका और खाद्य सुरक्षा का गंभीर संकट पैदा हो सकता है। इसलिए शासन-प्रशासन को प्रभावित किसानों और ग्रामीण परिवारों की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए शीघ्र राहत उपलब्ध करानी चाहिए। उन्होंने उम्मीद जताई कि प्रशासन प्रभावित क्षेत्रों का शीघ्र सर्वे कराकर किसानों और जरूरतमंद परिवारों को उचित सहायता उपलब्ध कराने की दिशा में आवश्यक कदम उठाएगा।

सड़क, नाली, महतारी सदन, शुद्ध पेयजल और स्ट्रीट लाइट की मांग रखी

खोपली के विकास कार्यों को लेकर विधायक ललित चंद्राकर से मिलीं सरपंच मंजू वर्मा एवं पंचगण

अंचल वर्मा - दुर्ग, उत्तई।
जनता के गोटा।
उत्तई - दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत खोपली के सर्वांगीण विकास एवं ग्रामीणों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ग्राम पंचायत की सरपंच मंजू फतेलाल वर्मा के नेतृत्व में पंचगणों के प्रतिनिधिमंडल ने दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के विधायक ललित चंद्राकर से सौजन्य मुलाकात की।
इस दौरान सरपंच मंजू फतेलाल वर्मा एवं पंचगणों ने ग्राम पंचायत खोपली में संचालित विकास कार्यों की जानकारी देते हुए गांव की आवश्यकताओं एवं



जनहित से जुड़े विभिन्न मुद्दों को विधायक के समक्ष प्रमुखता से रखा। प्रतिनिधिमंडल ने गांव की मुख्य सड़कों के सीमेंटीकरण, नाली निर्माण एवं बेहतर जल निकासी व्यवस्था, महतारी सदन निर्माण, शुद्ध पेयजल की समुचित

व्यवस्था तथा गलियों एवं प्रमुख स्थानों पर स्ट्रीट लाइट लगाने सहित विभिन्न विकास कार्यों की मांग की।
विधायक ने दिया विकास कार्यों को प्राथमिकता देने का आश्वासन
दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित

चंद्राकर ने प्रतिनिधिमंडल की सभी मांगों को गंभीरतापूर्वक सुना तथा ग्राम पंचायत खोपली के विकास कार्यों को प्राथमिकता देने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों का विकास और आमजन को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना प्राथमिकता है। ग्राम पंचायत खोपली के विकास में किसी प्रकार की कमी नहीं आने दी जाएगी। साथ ही, उन्होंने संबंधित विभागों के माध्यम से आवश्यक कार्यों पर शीघ्र कार्रवाई कराने की बात कही।
सरपंच मंजू फतेलाल वर्मा ने कहा कि ग्राम पंचायत खोपली के विकास, ग्रामीणों की समस्याओं के निराकरण तथा गांव में मूलभूत

सुविधाओं के विस्तार के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। विधायक के समक्ष प्रमुख मांगें रखी गई हैं, ताकि गांव में विकास कार्यों को गति मिल सके और ग्रामीणों को बेहतर सुविधाएं प्राप्त हो सकें।
इस अवसर पर उपसरपंच देवेन्द्र भारती सहित पंचगण रंजना वर्मा, संगीता पटेल, कुमारी बाई भारती, सिलोचना सिरमौर, गोदावरी देशलहरे, फूलमत सोनवानी, जानकी साहू, दामिनी साहू, कमलेश्वरी साहू, रमेश वर्मा, शुभम वर्मा, गजेन्द्र चंद्राकर, सुरेश यादव, लक्ष्मीचंद नारंग, अरुण चंद्राकर, संतोषी भारती, कल्याणी चंद्राकर एवं योगेंद्र साहू सहित वरिष्ठ कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

चरित्र पर संदेह बना हत्या की वजह! पत्नी की हत्या के आरोप में पति गिरफ्तार

बलरामपुर (जनता के गोट)
: बलरामपुर जिले के राजपुर थाना क्षेत्र के ग्राम कोटागहना में पत्नी की हत्या के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार, आरोपी को अपनी पत्नी के चरित्र पर संदेह था। इसी बात को लेकर हुए विवाद के दौरान उसने लकड़ी के डंडे से पत्नी के सिर पर वार कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करने के लिए भेज दिया है।

मोबाइल पर बातचीत को लेकर हुआ विवाद
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, मामले में ग्राम कोटागहना निवासी अनिल तिवारी ने 16 अक्टूबर 2026 को थाना राजपुर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया कि रामवृक्ष



कोरवा उर्फ पिंटू (35 वर्ष) ने अपनी पत्नी चिंतामणि कोरवा के साथ मारपीट कर उसकी हत्या कर दी। रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने अपराध क्रमांक 256/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) में मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की।
विवेचना के दौरान पुलिस ने

घटनास्थल का निरीक्षण किया और गवाहों के बयान दर्ज किए। पुलिस के मुताबिक, घटना के दिन चिंतामणि मोबाइल फोन पर किसी अज्ञात व्यक्ति से बातचीत कर रही थी। इसी दौरान अपने दो वर्षीय बेटे रयांश को साथ ले जाने की बात को लेकर भी विवाद हुआ। पुलिस का कहना है कि पत्नी के चरित्र पर संदेह और विवाद से नाराज होकर आरोपी ने घर में रखे लकड़ी के डंडे से उसके सिर पर वार किया, जिससे उसकी मौत हो गई।
डंडा और कपड़े जन्त, आरोपी गिरफ्तार
पुलिस ने विवेचना के दौरान घटना में इस्तेमाल किए गए लकड़ी के डंडे और मुक्तिका के कपड़े जन्त किए हैं। पुलिस के अनुसार, आरोपी को 17 अक्टूबर 2026 की रात 7:10 बजे गिरफ्तार किया गया।

जनपद सदस्य विनीता ठाकुर की पहल, सामुदायिक आयोजनों के लिए टेंट और बर्तन उपलब्ध

जनपद निधि से धार्मिक स्थलों को दी गई सामग्री, ग्रामीणों को सामाजिक एवं धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजन में मिलेगी सुविधा

भुजबल बघेल
बकावंड जनता के गोटा। विकासखंड बस्तर अंतर्गत जनपद पंचायत बस्तर के जनपद क्षेत्र क्रमांक 02 की जनपद सदस्य श्रीमती विनीता ठाकुर की पहल पर जनपद निधि से ग्रामीणों को सामुदायिक उपयोग के लिए टेंट एवं बर्तन उपलब्ध कराए गए हैं। इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाले सामाजिक, धार्मिक एवं सार्वजनिक आयोजनों के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, ग्राम तुरपुरा की जनपद सदस्य श्रीमती विनीता ठाकुर द्वारा जनपद निधि से उपलब्ध कराई गई टेंट एवं बर्तन सामग्री कुडकानारीन गुड़ी स्थित माता मंदिर, घाटी मुडीन दाई, झंडा माई तथा पल्लेभाटा स्थित दुलार दाई



मंदिर में सामुदायिक उपयोग के लिए प्रदान की गई हैं।
इस सामग्री के उपलब्ध होने से स्थानीय ग्रामीणों को धार्मिक अनुष्ठानों, सामाजिक कार्यक्रमों, सामूहिक आयोजनों एवं अन्य सार्वजनिक गतिविधियों के आयोजन में सुविधा मिलेगी। अब विभिन्न आयोजनों के दौरान टेंट और बर्तनों की व्यवस्था करने में ग्रामीणों को होने

वाली परेशानियों में कमी आएगी।
जनपद निधि के माध्यम से की गई इस पहल को ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक सुविधाओं के विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इससे ग्रामीणों को सामूहिक आयोजनों के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध होंगे और गांवों में सामाजिक सहभागिता को भी बढ़ावा मिलेगा।

पिता की हत्या के मामले में बेटे को उम्रकैद ! उत्तई के डोमन लाल को कोर्ट ने सुनाई सजा

दुर्ग पुलिस की विवेचना और अभियोजन की प्रभावी पैरवी से मिली दोषसिद्धि, ?1,000 का जुर्माना भी लगाया

अंचल वर्मा - दुर्ग, उत्तई। जनता के गोटा।
दुर्ग - छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में पिता की हत्या के मामले में अदालत ने आरोपी बेटे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
अपर सत्र न्यायालय, पाटन ने 16 अक्टूबर 2026 को आरोपी डोमन लाल यदु उर्फ चुन्नी लाल यदु (42 वर्ष), निवासी ग्राम गाड़ाडीह चौक, थाना उत्तई को भारतीय न्याय संहिता (ब्रह्म) की धारा 103 के तहत दोषी ठहराते हुए उम्रकैद और 1,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया। जुर्माना अदा नहीं करने पर उसे पांच माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतान होगा।
पिता पर प्राणघातक हमले के मामले में हुई कार्रवाई - पुलिस के मुताबिक, 21 अक्टूबर 2025 को थाना उत्तई क्षेत्र में पिता पर प्राणघातक हमला किए जाने से संबंधित मामले में अपराध क्रमांक 428/2025 दर्ज किया गया था। मामले की विवेचना



तत्कालीन थाना प्रभारी निरीक्षक महेश धव ने की। विवेचना के दौरान साक्ष्य जुटाए गए और आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद 22 दिसंबर 2025 को न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।
साक्ष्यों और दलीलों के आधार पर कोर्ट का फैसला
मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायालय, पाटन, जिला दुर्ग में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक शेखर वर्मा

ने पैरवी की। न्यायालय ने प्रस्तुत साक्ष्यों और अभियोजन के तर्कों पर विचार करने के बाद आरोपी को दोषसिद्ध कर आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
इस मामले में पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन, विवेचना पूरी कर समय पर अभियोग पत्र पेश करने और अभियोजन पक्ष की न्यायालय में पैरवी को महत्वपूर्ण माना गया है , अदालत के फैसले के साथ ही पिता की हत्या के इस प्रकरण में आरोपी को कठोर दंड मिला है।
दुर्ग पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि पारिवारिक विवादों और आपसी मतभेदों का समाधान हिंसा के बजाय संवाद एवं कानूनी प्रक्रिया से करें। किसी भी गंभीर घटना की सूचना तत्काल पुलिस को दें।
आरोपी: डोमन लाल यदु उर्फ चुन्नी लाल यदु, उम्र 42 वर्ष
निवासी: ग्राम गाड़ाडीह चौक, थाना उत्तई, जिला दुर्ग
सजा: आजीवन कारावास और ?1,000 अर्थदंड
फैसले की तारीख: 16 अक्टूबर 2026
न्यायालय: अपर सत्र न्यायालय, पाटन, जिला दुर्ग

जिला स्तरीय पठनवीर प्रतियोगिता 2026 में पाटन विकासखंड के बच्चों ने लहराया परचम

जिला स्तरीय पठनवीर प्रतियोगिता 2026 का आयोजन जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाइट) अछोटी, दुर्ग में किया गया। प्रतियोगिता में पाटन विकासखंड के प्रतिभागियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन कर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। इस उपलब्धि से विकासखंड का गौरव बढ़ा और शिक्षा जगत में हर्ष का माहौल रहा।
मुख्य अतिथि एवं अध्यक्षता-कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वरिष्ठ समाजसेवी श्री बिसरा राम यादव की रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता डाइट अछोटी के प्राचार्य महोदय ने की। कार्यक्रम में एससीईआरटी (SCERT) से आए गणमान्य सदस्य, एपीसी दुर्ग तथा डाइट के प्रोफेसर एवं व्याख्यातागण उपस्थित रहे। अतिथियों ने प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन करते हुए उनके उत्कृष्ट



प्रदर्शन की सराहना की।
प्रतियोगिता में विभिन्न विधाओं के अंतर्गत प्रतिभागियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। स्टोरी टेलिंग, पठन एवं स्पीड रीडिंग जैसी गतिविधियों के माध्यम से प्रतिभागियों ने अपनी भाषा दक्षता, अभिव्यक्ति कौशल और पठन क्षमता का प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करने वाले

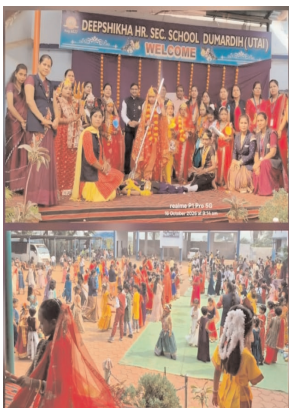
प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया।
- पठनवीर प्रतियोगिता 2026 में पाटन के विजेता बच्चे
स्टोरी टेलिंग:- प्रथम स्थान: रुद्रांश निषाद (शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला मोरिद)
द्वितीय स्थान: कुमारी रितिका (शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला कुगदा)

क्रिज:- द्वितीय स्थान: कुमारी चंचला (शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला खुडमुड़ी), कुमारी शैल देवी (शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला फेकारी)
स्पीड रीडिंग:- प्रथम स्थान: कुमारी कुमकुम (शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला फेकारी)
कार्यक्रम में इनकी रही विशेष उपस्थिति- इस अवसर पर सहायक विकासखंड शिक्षा अधिकारी श्रीमती आकांक्षा अग्रवाल, बीआरसी श्री गुनेश्वर प्रसाद वर्मा, सीएससी श्री हरिश्चंकर देवांगन, श्री निदेश कुमार साहू, श्रीमती इंदु सोनकर, श्रीमती प्रज्ञा गुप्ता, श्रीमती मीना सैयाम उपस्थित रहे। सभी ने प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन किया तथा उनकी उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त की।
कार्यक्रम में उपस्थित शिक्षकों एवं शिक्षा विभाग के प्रतिभागियों ने

इस प्रकार की प्रतियोगिताओं को विद्यार्थियों एवं शिक्षकों की प्रतिभा निखारने, पठन संस्कृति को बढ़ावा देने तथा शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया को अधिक महत्वपूर्ण बताया।
पाटन विकासखंड के लिए गौरव का क्षण- जिला स्तरीय प्रतियोगिता में मिली यह उपलब्धि क्षेत्र के लिए गौरवपूर्ण है। जिला शिक्षा अधिकारी, दुर्ग द्वारा भी पाटन विकासखंड की इस सफलता की सराहना की गई है। पाटन विकासखंड शिक्षा अधिकारी श्री डालेंद्र देवांगन ने इस उपलब्धि पर पाटन विकासखंड के बी आर सी वर्मा जी , सभी संकुल समन्वयको को और बच्चों के साथ-साथ शिक्षकों को भी बहुत-बहुत बधाई दी और कहा कि यह जीत और पदक आने वाले समय में और बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरणा का कार्य करेगी।

अंचल वर्मा - दुर्ग, उत्तई।
जनता के गोटा।

उत्तई - दीपशिखा विद्यालय डुमरडीह, उत्तई में नवरात्रि पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। दोनों ही पाली के विद्यार्थी नौ दुर्गा के विभिन्न रूपों में साक्षात दर्शन देकर अपनी प्राकट्य कारण देते हुए आतातयी राक्षसों का मर्दन कर असत्य एवं बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश दिए तथा जीत की खुशी को गरबा नृत्य के माध्यम से जाहिर करते हुए माँ शक्ति, माँ दुर्गा की आराधना की। इस अवसर पर दीपशिखा शिक्षण समिति के डायरेक्टर डी एल सिन्हा ने नवरात्रि पर्व की बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए पर्व की महत्ता को बताते हुए कहा कि जीवन में असुरी स्वभाव को हावी नहीं होने देना चाहिए। इससे बचने के लिए अपने जीवन में भक्ति, शक्ति एवं विश्वास को जागृत करना चाहिए।



विद्यालय के प्राचार्य के आर सिन्हा ने भी इस पर्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यदि हमारे जीवन में कोई कार्य असंभव सा प्रतीत होने लगे और हमारा आत्मविश्वास कमजोर पड़ने लगे तो ऐसी स्थिति में अपने आत्मबल, आत्मशक्ति को बढ़ाने के लिए माँ शक्ति एवं अपने आराध्य देव की उपासना कर उनसे शक्ति, ऊर्जा एवं

आशीर्वाद प्राप्त कर असम्भव को सम्भव कर सकने की बात कही।
उन्होंने कहा, अपने अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह एवं अहंकार रूपी राक्षस कभी-कभी नियंत्रण से बाहर होने लगता है इस परिस्थिति में ध्यान ,भजन, आराधना एवं उपासना से संयमित कर सम्मार्ग की ओर अग्रसर होना चाहिए। विद्यालय के शालानायक हर कुमार चंद्राकर ने बड़े ही रोचक अंदाज में नवरात्रि पर्व के बारे में बताते हुए कहा कि हम केवल नौ दिन ही माता की आराधना ही क्यों करें? मातृशक्ति हमेशा पूजनयोग एवं वंदनीय है। उन्हें देवी का दर्जा दी गई है। समाज में इसकी सार्थकता तभी है जब समाज मातृशक्ति को सम्मान, सुरक्षा एवं बराबरी का दर्जा दे। उन्होंने कहा, शक्ति हमारे अंदर भी है जो अन्याय के प्रति लड़ने एवं गिरकर पुनः उठने का साहस देता है।

शंकरपुर में धूमधाम से मना दसई करमा पर्व, आदिवासी संस्कृति की दिखी भव्य झलक

बलरामपुर (जनता के गोट)
: ग्राम पंचायत शंकरपुर में राजा चिंचोल सेवा समिति के बैनर तले दसई करमा पूजा पर्व पारंपरिक रीति-रिवाजों, आस्था और हर्षोल्लास के साथ धूमधाम से मनाया गया। आयोजन में आदिवासी समाज की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, पारंपरिक पहचान और सामाजिक एकजुटता का भव्य स्वरूप देखने को मिला। पर्व के माध्यम से समाज ने अपनी गौरवशाली परंपराओं को संरक्षित रखने और नई पीढ़ी तक पहुंचाने का संदेश दिया।
कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में रघुनाथनगर तहसीलदार उदयराज सिंह उपस्थित रहे। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में सर्व आदिवासी समाज वाइज़मगर के ब्लॉक अध्यक्ष सुखनाथ मराबी, छत्तीसगढ़ गोंड कर्मचारी कल्याण संघ के शिवकुमार आयाम, वरिष्ठ समाजसेवी रामवृक्ष जगत, गोंडवाना गोंड महासभा के जिलाध्यक्ष राजकुमार पोते तथा वाइज़मगर नगर पंचायत अध्यक्ष मान सिंह सहित जानसम्य नेताम और रामदेव जगत शामिल हुए।



आस्था, परंपरा और प्रकृति के सम्मान का प्रतीक है करमा पर्व
दसई करमा पूजा आदिवासी समाज की आस्था, प्रकृति के प्रति सम्मान और पीढ़ियों से चली आ रही सांस्कृतिक परंपराओं का महत्वपूर्ण प्रतीक है। यह पर्व समाज को अपनी जड़ों से जोड़ने के साथ आपसी भाईचारे, सहयोग और एकजुटता की भावना को मजबूत करता है। ऐसे आयोजन न केवल सांस्कृतिक विरासत को जीवित

रखते हैं, बल्कि नई पीढ़ी को अपने पूर्वजों की परंपराओं और सामाजिक मूल्यों से परिचित कराने में भी अहम भूमिका निभाते हैं।
शंकरपुर में आयोजित इस पर्व ने आदिवासी समाज की सांस्कृतिक पहचान और परंपराओं के संरक्षण के प्रति सामूहिक प्रतिबद्धता को सामने रखा। आयोजन में ग्रामीणों की सहभागिता ने पर्व के प्रति समाज की आस्था और उत्साह को प्रदर्शित किया।
समिति के पदाधिकारियों

सहित सैकड़ों ग्रामीण हुए शामिल
कार्यक्रम को सफल बनाने में राजा चिंचोल सेवा समिति के अध्यक्ष राजू मरकाम, संरक्षक रामनारायण सिंह आयाम, सचिव देवकरण सिंह आयाम, सहसचिव हरिबल आयाम, कुंजबिहारी सिंह आयाम, तेजकुमारी आयाम, रामसुन्दर सिंह पोया, पूनम सिंह, सीता कुंवर, कमलेश धुर्वे और अनिल आयाम सहित समिति के सदस्यों की भूमिका रही। इस अवसर पर सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण महिला-पुरुष उपस्थित रहे।

बाढ़ प्रभावितों की मदद के लिए धाकड़ समाज कल्याण समिति ने मुख्यमंत्री राहत कोष में दिए 21 हजार रुपये

कलेक्टर को सौंपा चेक, अध्यक्ष नरेंद्र सिंह ठाकुर ने प्रभावित परिवारों के पुनर्वास और मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था सुनिश्चित करने की अपील की

बकावंड जनता के गोटाबस्तर में आई भीषण बाढ़ से प्रभावित परिवारों की सहायता के उद्देश्य से बस्तर धाकड़ समाज कल्याण समिति, जिला बस्तर (पंजीयन क्रमांक 10281) ने मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए 21 हजार रुपये की सहयोग राशि प्रदान की है। समिति के पदाधिकारियों ने कलेक्टर, जिला बस्तर को आवेदन सौंपकर चेक क्रमांक 665013 के माध्यम से राशि दी। साथ ही आग्रह किया कि निर्धारित प्रक्रिया के तहत राशि मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा कर बस्तर जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जरूरतमंद परिवारों की सहायता के लिए उपयोग सुनिश्चित किया जाए।



बाढ़ के दौरान प्रभावित परिवारों को मकानों, घरेलू सामान और आजीविका से जुड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। आपदा के बाद भी कई परिवारों के लिए सामान्य जनजीवन की ओर लौटना चुनौतीपूर्ण रहता है। ऐसे समय में आर्थिक सहयोग और बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता प्रभावित लोगों को फिर से अपने पैरों पर खड़े होने में मदद करती है। धाकड़ समाज कल्याण समिति ने इसी सामाजिक जिम्मेदारी और मानवीय संवेदना के साथ मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए सहयोग राशि प्रदान

की है।
समिति के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि प्राकृतिक आपदा से प्रभावित परिवारों को राहत देने के साथ उनके पुनर्वास पर भी ध्यान देना आवश्यक है। उन्होंने शासन-प्रशासन से अपील की कि बस्तर जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में हुए नुकसान का आकलन कर पात्र परिवारों को नियमानुसार राहत एवं पुनर्वास सहायता उपलब्ध कराई जाए। प्रभावित क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल, स्वास्थ्य सुविधाओं और अन्य आवश्यक मूलभूत सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के

लिए भी प्रभावी कदम उठाए जाएं।
नरेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि आपदा के प्रभाव से उबरने में प्रभावित परिवारों को समय और सहयोग दोनों की आवश्यकता होती है। ऐसे में शासन-प्रशासन के प्रयासों के साथ सामाजिक संगठनों और समाज के सक्षम लोगों की भागीदारी भी महत्वपूर्ण है। उन्होंने समाज के लोगों से अपनी सामर्थ्य के अनुसार जरूरतमंद परिवारों की सहायता करने की अपील करते हुए कहा कि सामाजिक एकजुटता से कठिन परिस्थितियों का सामना करने वाले लोगों को संबल मिलता है। बस्तर धाकड़ समाज कल्याण समिति की ओर से दी गई यह सहयोग राशि बाढ़ प्रभावित परिवारों की सहायता के लिए सामाजिक सहभागिता का एक प्रयास है। समिति ने इस पहल के माध्यम से आपदा प्रभावित लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए उनके पुनर्वास और सामान्य जनजीवन की बहाली के लिए सहयोग की भावना जताई।

संपादकीय

ममता बनर्जी की सुरक्षा में सेंध की कोशिश, उठे सवाल

इस घटना की प्रारंभिक जांच के बाद पुलिस का कहना है कि आरोपी महिला का ममता बनर्जी पर हमला करने का इरादा नहीं था, बल्कि वह उनसे मिलना चाहती थी। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर कोलकाता में उनके आवास के पास एक महिला द्वारा हमले की कोशिश करने की घटना ने सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल

खड़े कर दिए हैं। अगर किसी राजनीतिक दल के प्रमुख नेता पर ही सरेआम हमले का प्रयास किया जाता है, तो आम आदमी खुद को सुरक्षित कैसे महसूस कर पाएगा! पार्टी के ममता समर्थक धड़े का आरोप है कि संबंधित महिला के हाथ में चाकू थाहालाकि इसकी सच्चाई गहन जांच के बाद ही सामने आएगी, लेकिन सवाल है कि आरोपी महिला ममता के

सुरक्षा घरे के इतने करीब कैसे पहुंच गई? इस बात की जांच-पड़ताल भी जरूरी है कि सुरक्षा व्यवस्था में कहां चूक हुई और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए भविष्य में क्या कदम उठाए जा सकते हैं। राज्य में पिछले लंबे समय से राजनीतिक हिंसा की खबरें भी आती रही हैं, लिहाजा पुलिस को हर पहलू से इस घटना की छानबीन करनी चाहिए, ताकि सच सबके

सामने आ सके।खबरों के मुताबिक, ममता बनर्जी पर बीते मंगलवार को उस वक्त हमले की कोशिश की गई, जब वह दुर्गा पूजा का उद्घाटन करने जा रही थीं। हालांकि, सुरक्षा कर्मियों और वहां मौजूद पार्टी कार्यकर्ताओं ने आरोपी महिला को पकड़ कर पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं, इस घटना की प्रारंभिक जांच के बाद पुलिस का कहना है कि आरोपी

महिला का ममता बनर्जी पर हमला करने का इरादा नहीं था, बल्कि वह उनसे मिलना चाहती थी। मगर यह सवाल भी महत्वपूर्ण है कि क्या किसी प्रमुख नेता की सुरक्षा से जुड़े मामले को महज राजनीतिक आरोप मानकर उसकी गंभीरता को नजरअंदाज किया जा सकता है? कायदे से इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और अगर सुरक्षा में चूक का कोई

मामला बनता है, तो उसमें भी जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए।पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा को लेकर उठ रहे सवालों के बीच इस घटना की संवेदनशीलता को समझना जरूरी है। लोकतंत्र में राजनीतिक मतभेद होना सामान्य बात है, लेकिन जब असहमति हिंसा की दहलीज तक पहुंच जाए, तो खतरा किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता।

इस वर्ष बारिश में गिरावट की वजह से भावी संकट को लेकर बढ़ती फिफ़र स्वाभाविक है। मगर फिलहाल चिंता का कारण केवल बारिश नहीं, बल्कि ज़मीन पर उपलब्ध पानी को संभालने की हमारी घटती क्षमता है। देश के प्रमुख जलाशयों का जलस्तर तेज़ी से नीचे जाना और दूसरी ओर उन्हीं जलाशयों की भंडारण क्षमता का गाद के कारण लगातार कम होते जाना आने वाले समय के लिए गंभीर संकेत है। सवाल यह नहीं है कि मानसून इस बार कितना अच्छा रहा, बल्कि बड़ा सवाल यह है कि मानसून से मिलने वाले पानी को हम कितना बचा पाए। गौरतलब है कि केंद्रीय जल आयोग 166 प्रमुख जलाशयों के जलस्तर की नियमित निगरानी करता है। इन जलाशयों की कुल क्षमता 183.565 अरब घन मीटर है। मध्य-मई की स्थिति के अनुसार इनमें करीब 63 बीसीएम पानी ही बचा था। यानी लगभग 34.45 फीसद की कमी है।

(बलकार सिंह पुनियां) देश में 6,628 बड़े बांध हैं। इनमें से 1,681 बांध 50 वर्ष से अधिक पुराने हैं और 291 बांध सौ वर्ष से भी अधिक पुराने हैं। यानी देश के लगभग 26 फीसद बांध आधी सदी से अधिक पुराने हैं।

इस वर्ष बारिश में गिरावट की वजह से भावी संकट को लेकर बढ़ती फिफ़र स्वाभाविक है। मगर फिलहाल चिंता का कारण केवल बारिश नहीं, बल्कि जमीन पर उपलब्ध पानी को संभालने की हमारी घटती क्षमता है। देश के प्रमुख जलाशयों का जलस्तर तेज़ी से नीचे जाना और दूसरी ओर उन्हीं जलाशयों की भंडारण क्षमता का गाद के कारण लगातार कम होते जाना आने वाले समय के लिए गंभीर संकेत है। सवाल यह नहीं है कि मानसून इस बार कितना अच्छा रहा, बल्कि बड़ा सवाल यह है कि मानसून से मिलने वाले पानी को हम कितना बचा पाए।

गौरतलब है कि केंद्रीय जल आयोग 166 प्रमुख जलाशयों के जलस्तर की नियमित निगरानी करता है। इन जलाशयों की कुल क्षमता 183.565 अरब घन मीटर है। मध्य-मई की स्थिति के अनुसार इनमें करीब 63 बीसीएम पानी ही बचा था। यानी लगभग 34.45 फीसद। इससे स्पष्ट है कि गर्मी के चरम दौर में देश के प्रमुख जलाशयों का लगभग दो-तिहाई भंडारण खाली हो चुका था। कई राज्यों में स्थिति इससे भी अधिक चिंताजनक रही और अनेक बांधों में पानी काफी कम हो गया।

यह स्थिति इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि जलाशय केवल पानी जमा करने की जगह नहीं हैं। उनसे खेतों की सिंचाई होती है, शहरों और गांवों को पेयजल मिलता है तथा बिजली का उत्पादन भी होता है। जलाशयों में पानी कम होने का अर्थ है कि कृषि, पेयजल और ऊर्जा पर एक साथ दबाव बढ़ना। गर्मी के दिनों में पानी की मांग स्वाभाविक रूप से बढ़ती है। अगर मानसून आने में देरी होती है या वर्षा सामान्य से कम या असमान रहती है, तो यह दबाव और अधिक बढ़ सकता है।

देश की जल समस्या का शायद सबसे गंभीर और अपेक्षकृत कम चर्चित पहलू जलाशयों में लगातार बढ़ती गाद है। केंद्रीय जल आयोग द्वारा तैयार भारत में जलाशयों में गाद जमाव संबंधी संकलन-2024 में 548 जलाशयों के आंकड़ों का अध्ययन किया गया, जिनमें से 439 जलाशयों के आंकड़े विश्लेषण के लिए उपयुक्त पाए गए। एक अध्ययन के अनुसार, गाद जमने के कारण इन जलाशयों की सकल भंडारण क्षमता में औसतन 19.24 फीसद की कमी आ चुकी है। वहीं, जलाशयों की भंडारण क्षमता में प्रत्येक वर्ष औसतन 0.74 फीसद की कमी दर्ज की जा रही है।

यह आंकड़ा भविष्य की भयावह तस्वीर समझने के लिए पर्याप्त है। अगर जलाशय में पानी पहुंचाने वाली नदियां और बरसाती धाराएं

अपने साथ मिट्टी एवं तलछट लाती रहें तथा जलाशयों में गाद जमा होती रहे, तो कुछ वर्षों बाद अच्छी बारिश होने पर भी हमारे पास पानी रखने की पर्याप्त क्षमता नहीं होगी। यानी एक तरफ वर्षा की अनिश्चितता और दूसरी तरफ घटती भंडारण क्षमता। यह दोहरी चुनौती है।

ऊपर की मिट्टी को बहने से नहीं रोका गया, तो नीचे जलाशयों से गाद निकालने का काम लगातार चलता रहेगा और समस्या कभी खत्म नहीं होगी।

कृषि क्षेत्र में भी दुष्टक्रोण बदलना होगा। भारत में पानी का सबसे बड़ा उपयोग कृषि में होता है। ऐसे में कम पानी में अधिक उत्पादन की



यह समस्या पुराने जलाशयों में अधिक गंभीर हो सकती है। नेशनल रजिस्टर ऑफ सोसिएटाइड हैम्स-2025 के अनुसार देश में 6,628 बड़े बांध हैं। इनमें से 1,681 बांध 50 वर्ष से अधिक पुराने हैं और 291 बांध सौ वर्ष से भी अधिक पुराने हैं। यानी देश के लगभग 26 फीसद बांध आधी सदी से अधिक पुराने हैं। उम्र अपने आप में किसी बांध को असुरक्षित नहीं बनाती, लेकिन समय बीतने के साथ संरचनात्मक रखरखाव, जलाशय की क्षमता, गाद और जलग्रहण क्षेत्र में बदलाव की नियमित समीक्षा जरूरी है।

गाद की समस्या का समाधान केवल जलाशय से गाद निकालने तक सीमित नहीं हो सकता। दरअसल, गाद का बड़ा स्रोत जलग्रहण क्षेत्र में मिट्टी का कटाव है। इसलिए पहाड़ियों और नदी घाटियों में वनों की कटाई, भूमि क्षरण, अवैज्ञानिक खेती, निर्माण गतिविधियों और जलग्रहण क्षेत्रों के कमजोर प्रबंधन को रोकना भी उतना ही आवश्यक है। अगर

दिशा में फसल विविधीकरण, सूक्ष्म सिंचाई, ‘ड्रिप’ और ‘स्प्रिंकलर’ जैसी तकनीकों का विस्तार जरूरी है। जिस क्षेत्र में पानी सीमित है, वहां अत्यधिक जल मांग वाली फसलों को बढ़ावा जल संकट को बढ़ाएगा।

वर्ष 2025 के दौरान देश में बांधों का मानसून पूर्व और उसके बाद निरीक्षण किया गया। इसमें तीन बांधों को सबसे गंभीर श्रेणी-एक तथा 216 बांधों को श्रेणी-दो में रखा गया। ये आंकड़े स्पष्ट करते हैं कि बांधों की सुरक्षा को केवल उनके निर्माण के समय ही नहीं, बल्कि उनकी पूरी समयावधि के दौरान प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। नियमित निरीक्षण, समयबद्ध रखरखाव और आवश्यकता अनुसार पुनर्वास से ही बांधों की सुरक्षा और उनकी उपयोगिता लंबे समय तक सुनिश्चित की जा सकती है।

भारत ने बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021 और बांध पुनर्वास एवं सुधार परियोजना जैसे कदमों से इस दिशा में संस्थागत व्यवस्था को मजबूत करने का प्रयास किया है। अब

जरूरत इस बात की है कि इन व्यवस्थाओं का प्रभाव राज्यों और स्थानीय स्तर पर भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे। प्रत्येक बड़े बांध के लिए नियमित निरीक्षण, समयबद्ध रखरखाव, आपातकालीन कार्ययोजना, जलाशय की वास्तविक भंडारण क्षमता का आकलन तथा गाद प्रबंधन को अनिवार्य रूप से जल प्रबंधन व्यवस्था का हिस्सा बनाया जाना चाहिए।

दरअसल, जल संकट का स्थायी समाधान केवल अच्छी बारिश नहीं है। मानसून अच्छा हो, तो भी यदि हम पानी को रोक नहीं पाए और जलाशयों की क्षमता घटती रही तथा भूजल का अत्यधिक दोहन जारी रहा, तो अगले कुछ वर्षों में समस्या गंभीर रूप से हमारे सामने खड़ी होगी। दूसरी ओर, अगर मानसून कमजोर रहा, तो मौजूदा जल भंडारण की सीमाएं और स्पष्ट हो जाएंगी। इसलिए मानसून का इंतजार अपनी जगह है, लेकिन जल प्रबंधन को मानसून से अलग एक निरंतर राष्ट्रीय अभियान बनाना होगा। जलाशयों की निगरानी केवल जलस्तर मापने तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। वास्तविक भंडारण क्षमता, गाद की मात्रा, जलग्रहण क्षेत्र और भविष्य की जल मांग का भी नियमित आकलन होना चाहिए।

इस समस्या पर सबसे बड़ी जरूरत सोच बदलने की है। पानी को असीमित प्राकृतिक संसाधन मानने के बजाय सीमित और मूल्यवान संपदा समझना होगा। जिस पानी को आज हम व्यर्थ बहने देते हैं, वही कल खेत, गांव, शहर और उद्योग के लिए जीवनरक्षा बन सकता है। देश के पास बांधों का विशाल नेटवर्क है। इसकी संग्रहण क्षमता 253.95 अरब घन मीटर है। यह क्षमता हमारी बड़ी ताकत है, लेकिन इसकी उपयोगिता तभी कायम रहेगी, जब हम जलाशयों की उम्र, गाद और घटती क्षमता को गंभीरता से लें। आज जरूरत नए जलाशय गिनने से अधिक मौजूदा जलाशयों की बची हुई क्षमता बचाने की है।

जल सुरक्षा केवल बारिश से नहीं आएगी। इसके लिए जलग्रहण क्षेत्रों का संरक्षण, गाद नियंत्रण, पुराने बांधों का पुनर्वास, वर्षा जल संचयन, भूजल पुनर्भरण और पानी के विवेकपूर्ण उपयोग को एक साझा राष्ट्रीय कार्यक्रम बनाना होगा। आखिरकार सवाल यह नहीं है कि आसमान से कितना पानी बरसेगा। सवाल यह है कि धरती पर गिरने वाली हर बूंद में से हम कितनी बूंदें आने वाली पीढ़ियों के लिए सहेज पाएंगे।

फीबीज कल्चर या सामाजिक सुरक्षा? जानिए भारत के विकास और चुनावी वादों की असल चुनौती

(सुधीर कुमार) भारत में असली चुनौती लोक कल्याण और राजकोषीय विवेक में संतुलन की है। मुफ्त चुनावी वादों के बजाय शिक्षा, स्वास्थ्य व रोजगार में दीर्घकालिक निवेश ही वास्तविक नागरिक सशक्तीकरण और टिकाऊ विकास है।

देश के विकास में एक बड़ी चुनौती लोक कल्याण और राजकोषीय विवेक के बीच संतुलन बनाने की है। एक ओर आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सामाजिक सहायता जैसी व्यवस्थाएं हैं, तो दूसरी ओर चुनावों में तत्काल लाभ वाले वादे भी सामने आते हैं। ऐसे में यह तय करना जरूरी है कि लोक कल्याण कहाँ तक सामाजिक अधिकार है और किस बिंदु पर वह राजकोषीय विवेक की परीक्षा बन जाता है। भारतीय संविधान कल्याणकारी राज्य की दिशा स्पष्ट करता है।

प्रस्तावना सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का संकल्प रखती है। साथ ही ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाने का मार्ग प्रशस्त किया गया है, जिसमें लोक कल्याण बढ़े और आय, सुविधाओं तथा अवसरों की असमानता न रहे। इसके अलावा आजीविका, संसाधनों के व्यापक हित में वितरण और आर्थिक व्यवस्था में धन के अत्यधिक संकेंद्रण को रोकने जैसे उद्देश्यों का उल्लेख भी किया गया है।

ये प्रावधान न्यायालय में सीधे प्रवर्तनीय नहीं हैं और संविधान इन्हें शासन में मूलभूत मानता है। इसलिए सामाजिक सुरक्षा को महज राजनीतिक दान समझना संविधान की कल्याणकारी दृष्टि को संकुचित करने जैसा होगा। इसी संदर्भ में जीवन के अधिकार को भी केवल शारीरिक अस्तित्व तक सीमित नहीं माना गया है। संविधान जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करता है और छह से चौदह वर्ष के बच्चों के लिए निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है। सर्वोच्च न्यायालय ने भी एक महत्वपूर्ण फैसले में गरिमापूर्ण जीवन को भोजन, वस्त्र, आवास जैसी बुनियादी आवश्यकताओं से जोड़ा था। ऐसे में गरीब नागरिकों को न्यूनतम गरिमा के साथ जीवन जीने में सक्षम बनाने वाली सार्वजनिक व्यवस्था को सामान्य चुनावी ‘मुफ्त सौगात’ मानना उचित नहीं होगा। यहाँ से सामाजिक सुरक्षा और मुफ्त सौगात के बीच जरूरी भेद उभरता है। अच्छी सामाजिक नीति वह है, जो व्यक्ति की क्षमता बढ़ाती है, जोखिम कम करती है और उसे भविष्य में अधिक आत्मनिर्भर बनने का अवसर देती है।

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छ पेयजल, रोजगार गारंटी और गरीबों के लिए लक्षित

सहायता सार्वजनिक निवेश हैं। इनका लाभ पूरे समाज और अर्थव्यवस्था को मिलता है। इसके विपरीत ऐसी योजनाओं पर सवाल उठाना स्वाभाविक है, जिनमें लाभ का संबंध किसी स्पष्ट सामाजिक लक्ष्य, आवश्यकता या दीर्घकालिक क्षमता निर्माण से नहीं है। मगर किसी वस्तु या सेवा का मुफ्त होना अपने आप में उसे लोकलुभावन या अनुयादक नहीं बना देता।

मुफ्त बिजली की सीमित सहायता, छत्र को डिजिटल उपकरण, किसान को सिंचाई सहायता या महिला को परिवहन में दियायत के प्रभाव अलग-अलग हो सकते हैं। उनका मूल्यांकन पात्रता, लागत और परिणामों के आधार पर होना चाहिए। महत्वपूर्ण है कि खर्च का उद्देश्य क्या है और उससे सार्वजनिक हित कितना हासिल होता है।

चुनावी घोषणापत्रों को लेकर कानून और न्यायपालिका का रुख भी यही जटिलता दिखाता है। वर्ष 2013 में एक मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि चुनावी घोषणापत्र के वादों को जनप्रतिनिधित्व नौतून, 1951 की धारा 123 के तहत भ्रष्ट आचरण नहीं माना जा सकता। साथ ही अदालत ने निर्वाचन आयोग को राजनीतिक दलों से परामर्श कर घोषणापत्रों के लिए दिशा-निर्देश बनाने को कहा था।

निर्वाचन आयोग के वर्तमान दिशा-निर्देश कल्याणकारी योजनाओं के वादों पर आपत्ति नहीं करते, लेकिन राजनीतिक दलों से अपेक्षा करते हैं कि वे ऐसे वादों से बचें, जो चुनाव प्रक्रिया की शुचिता या मतदाताओं के स्वतंत्र निर्णय को प्रभावित करें। मुफ्त सौगातों को लेकर वर्ष 2022 में सर्वोच्च न्यायालय के सामने उठी बहस ने इस प्रश्न को फिर राष्ट्रीय विमर्श के केंद्र में ला दिया। मुद्दा केवल यह नहीं था कि कोई योजना मुफ्त है या नहीं, बल्कि यह था कि ऐसी घोषणाओं के वित्तीय प्रभाव, राजकोषीय स्थिरता और चुनावी समानता का आकलन कैसे हो। जोखिम तब है, जब ऐसी प्रतिबद्धताएं जताई जाएं, जिनके स्थायी राजस्व स्रोत न हों और जिनका भार शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे या रोजगार सृजन पर पड़े। हर सबसिडी को आर्थिक अपव्यय कहना भी उचित नहीं। कृषि, खाद्य, ऊर्जा या परिवहन में लक्षित सहायता सामाजिक स्थिरता और आर्थिक अवसरों का साधन बन सकती है। इसलिए सवाल ‘सबसिडी बनाम विकास’ का नहीं, बल्कि बेहतर प्राथमिकताओं, लक्षित लाभ और टिकाऊ वित्त का है। दुनिया के कुछ अनुभव इस बहस को उपयोगी संदर्भ देते हैं। ब्राजील का बोल्सा फमीलिया नकद सहायता को शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी शर्तों से जोड़ने वाला प्रमुख उदाहरण रहा है।

भारत के पास वैज्ञानिक प्रतिभाएं भरपूर, फिर भी क्यों नहीं हो पा रहीं बड़ी खोज?

वैज्ञानिक प्रतिभाओं की इतनी बड़ी संख्या होने के बावजूद भारत को नोबेल पुरस्कार ना के बराबर क्यों मिलते हैं? लेकिन शायद इससे भी ज्यादा जरूरी सवाल यह है कि दुनिया में बड़े वैज्ञानिक बदलाव लाने वाले देश ऐसा क्या अलग कर रहे हैं? और हमारे वैज्ञानिकों के रास्ते में कौन-सी बाधाएं हैं?इसका जवाब सिर्फ पैसा नहीं है, हालांकि पैसे की अहमियत जरूर है। अमेरिका अपने सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का करीब 3.4 फीसदी हिस्सा शोध और विकास पर खर्च करता है। जर्मनी 3 फीसदी से ज्यादा, जापान 3.5 फीसदी से अधिक और दक्षिण कोरिया 5 फीसदी से ज्यादा खर्च करता है।

(कामिनी वालिया)

चीन का उदाहरण अहम है। शोध और विकास पर उसका निवेश बढ़ा है और इसके साथ ही वह दुनिया में सस्ती तकनीक का एक बड़ा आपूर्तिकर्ता बन गया है। हर साल अक्टूबर में नोबेल पुरस्कारों की घोषणा होते ही भारत में एक सवाल फिर उठने लगता है। वैज्ञानिक प्रतिभाओं की इतनी बड़ी संख्या होने के बावजूद भारत को नोबेल पुरस्कार ना के बराबर क्यों मिलते हैं? लेकिन शायद इससे भी ज्यादा जरूरी सवाल यह है कि दुनिया में बड़े वैज्ञानिक बदलाव लाने वाले देश ऐसा क्या अलग कर रहे हैं? और हमारे वैज्ञानिकों के रास्ते में कौन-सी बाधाएं हैं?इसका जवाब सिर्फ पैसा नहीं है, हालांकि पैसे की अहमियत जरूर है। अमेरिका अपने सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का करीब 3.4 फीसदी हिस्सा शोध और विकास पर खर्च करता है। जर्मनी 3 फीसदी से ज्यादा, जापान 3.5 फीसदी से अधिक और दक्षिण कोरिया 5 फीसदी से ज्यादा खर्च करता है। चीन भी इस मद में जीडीपी का करीब 2.7 फीसदी खर्च करने के करीब पहुंच रहा है। इसके मुकाबले भारत में शोध और विकास पर कुल खर्च जीडीपी का महज 0.64 फीसदी है।

लेकिन इससे भी ज्यादा अहम बात यह है कि शोध के लिए पैसा कौन देता है। भारत में शोध और विकास पर होने वाले कूल खर्च का करीब 40 फीसदी हिस्सा उद्योग जगत से आता है। अमेरिका और चीन में यह हिस्सेदारी करीब तीन-चौथाई है। यानी भारत में शोध का दायरा भी छोटा है और

इसमें निजी क्षेत्र की भागीदारी भी कम है।

इसके साथ ही वैज्ञानिकों पर लगातार दबाव बढ़ रहा है कि वे नई तकनीकों विकसित करें, उत्पाद बनाएं, शोध को कारोबार में बदलें और समस्याओं का समाधान निकालें। देश की जरूरतों के लिहाज से ये लक्ष्य जरूरी हैं, लेकिन तकनीक कोई ऐसी चीज नहीं है, जिसे मांग



के मुताबिक तुरंत तैयार कर दिया जाए। हम शोध के आखिरी चरणों पर ज्यादा जोर दे रहे हैं, जबकि शुरुआत में होने वाले बुनियादी शोध में जरूरत के मुताबिक निवेश नहीं कर रहे हैं।

बुनियादी विज्ञान पर ध्यान देने की जरूरत: मिसाल के तौर पर, बीमारी की

जांच करने वाला कोई उपकरण विकसित करने से पहले कई साल तक उस बीमारी की प्रकृति, रोगणु के व्यवहार, शरीर की प्रतिक्रिया, जैविक संकेतकों और अन्य प्रक्रियाओं पर काम करना पड़ सकता है। तभी जाकर कोई उत्पाद तैयार करना संभव होता है। बुनियादी विज्ञान वह आधार है, जहां से नए विचार और आविष्कार जन्म

लेते हैं। भारत को अपनी शोध व्यवस्था में बदलाव की शुरुआत यहीं से करनी होगी। सबसे पहले, सरकार और शोध से जुड़ी एजेंसियों को बुनियादी विज्ञान के लिए अलग से धन की व्यवस्था करनी चाहिए। प्रतिस्पर्धा के आधार पर मिलने वाली शोध राशि का एक तय हिस्सा ऐसे शोध के लिए

रखा जाना चाहिए, जिनके सवाल वैज्ञानिक खुद चुनें और जिनका मकसद अपनी जिज्ञासा के आधार पर नई खोज करना हो। ऐसे हर शोध से पेटेंट, उत्पाद या तकनीक तैयार करने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए।

दूसरा, शोध के लिए मिलने वाली राशि को तीन स्पष्ट हिस्सों में बांटना चाहिए—नई खोज, खोज को उपयोगी तकनीक में बदलना और उसका व्यावहारिक इस्तेमाल। इन तीनों के लिए अलग-अलग समय-सीमा और सफलता के मानक तय होने चाहिए। तीसरा, भारत को ऐसे शोध के लिए लंबे समय तक आर्थिक मदद देनी चाहिए।

वैज्ञानिक काम की सख्त समीक्षा जरूर हो, लेकिन प्रशासनिक दखल और छोटी-छोटी बातों पर निगरानी कम होनी चाहिए। चौथा, देश में शोध की साझा सुविधाओं का राष्ट्रीय ढांचा तैयार करना जरूरी है। जीनोम, प्रोटीन, उन्नत इमेजिंग, जैविक नमूनों के भंडार, संरचनात्मक जीवविज्ञान, एआई और कंप्यूटिंग जैसी सुविधाएं अलग-अलग संस्थानों के वैज्ञानिकों को आसानी से उपलब्ध होनी चाहिए।

इसके अलावा, हमें शोध को देखने और वैज्ञानिकों के काम का आकलन करने का तरीका भी बदलना होगा। शोध पत्रों की संख्या, पत्रिकाओं का प्रभाव, पेटेंट और शोध के लिए मिली राशि का कितना इस्तेमाल हुआ, इन सबके आंकड़े जुटाना आसान है। लेकिन इनसे यह पता नहीं चलता कि वैज्ञानिक ने कोई महत्वपूर्ण नई खोज की है या नहीं। वैज्ञानिकों के काम का आकलन करते समय उनकी मौलिकता,

शोध के नतीजों को दोबारा हासिल कर पाने की क्षमता, उनके उठाए सवालों की अहमियत और नए ज्ञान के निर्माण को महत्व देना चाहिए।

इसके साथ ही उपयोगी आंकड़े, शोध मंच और तकनीक विकसित करने के काम तथा विज्ञान या स्वास्थ्य नीति पर शोध के असर को भी मान्यता मिलनी चाहिए। इसके लिए शोध की पूरी प्रक्रिया को सही ढंग से तैयार करना होगा।

चीन से सबक: चीन का उदाहरण इस मामले में अहम सबक देता है। शोध और विकास पर उसका निवेश बढ़ा है और इसके साथ ही वह दुनिया में सस्ती तकनीक का एक बड़ा आपूर्तिकर्ता बन गया है। 2024 में दुनिया के करीब 80 फीसदी सौर ऊर्जा पैनल मॉड्यूल और बैटरी सेल चीन में बने। वहीं, 2025 में दुनिया में बनने वाली इलेक्ट्रिक कारों में चीन की हिस्सेदारी करीब 70 फीसदी तक पहुंच गई। इससे यह सबक मिलता है कि नई खोजों को इंजीनियरिंग, विनिर्माण और बाजार से जोड़ना कितना जरूरी है। भारत के पास एक बड़ी प्राकृतिक ताकत है। यहां की विशाल और विविध आबादी वैज्ञानिक शोध के लिए व्यापक अवसर देती है। इसलिए हमें ऐसी व्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखना चाहिए, जो युवा वैज्ञानिकों को किसी नए और लोक के हटकर सवाल पर 10 या 15 साल तक काम करने का मौका दे। वे असफल हों, अपनी दिशा बदलें और फिर से कोशिश करें, लेकिन तुरंत कोई उत्पाद तैयार न कर पाने के लिए उन्हें नुकसान न उठाना पड़े।

आज मध्यरात्रि निकलेगी खप्पर यात्रा, तीन देवी मंदिरों से निकलेगी खप्पर, पुलिस की चौक चौबंद सुरक्षा

तीन मंदिरों से निकलेगी खप्पर

कवर्धा/जनता के गोठ। शारदीय नवरात्रि की महाअष्टमी 19 अक्टूबर को है और दशहरा 20 अक्टूबर को मनाया जाएगा। कवर्धा नगर में अष्टमी की मध्यरात्रि को तीन सिद्धपीठ देवी मंदिरों-मां दंतेश्वरी, मां चंडी और मां परमेश्वरी-से खप्पर निकाली जाएगी। यह करीब 150 साल पुरानी अनूठी परंपरा है, जिसमें देवी मां खप्पर के रूप में नगर भ्रमण करती हैं। हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए उमड़ने वाले हैं। परंपरा के अनुसार अष्टमी की मध्यरात्रि को मां दंतेश्वरी, मां चंडी और मां परमेश्वरी मंदिर से क्रमशः खप्पर निकाली जाती है। पुजारी एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में जलता हुआ अग्नि खप्पर लेकर निकलते हैं। यह खप्पर देवी का प्रतीक माना जाता है। पंडों द्वारा सात काल,



देवी-देवताओं और वीर बैतालों को मंत्रोच्चार के साथ आमंत्रित कर खप्पर में विराजमान किया जाता है। श्रद्धालु इस पल को साक्षात् देवी के दर्शन के रूप में मानते हैं।

परंपरागत मार्ग से होगा नगर भ्रमण खप्पर निर्धारित मार्ग से होकर गुजरता है। इसमें पाली पारा, ठाकुर पारा, ऋषभ देव चौक, जयस्तंभ चौक, आंबेडकर चौक,

मां महामाया मंदिर, भोजली तालाब, रानी दुर्गावती चौक, राजमहल चौक, शीतला चौक, करपात्री चौक और कचहरी पारा जैसे स्थान शामिल हैं। अंत में खप्पर वापस

मंदिर प्रांगण पहुंचता है। रास्ते भर भक्त जयकारे लगाते हुए दर्शन करते हैं।

150 साल पुरानी परंपरा* कवर्धा में यह परंपरा लगभग डेढ़ सौ वर्षों से निरंतर जारी है। बुजुर्गों के अनुसार नवरात्रि की अष्टमी की मध्यरात्रि को ही खप्पर निकाला जाता है। मान्यता है कि खप्पर के नगर भ्रमण से नगर में किसी प्रकार की आपदा या बीमारी प्रवेश नहीं कर पाती और सुख-शांति बनी रहती है। देश में अब यह परंपरा केवल कवर्धा में ही जीवित बताई जाती है। मां दंतेश्वरी, मां चंडी और मां परमेश्वरी मंदिर सिद्धपीठ माने जाते हैं।

भीड़ और व्यवस्था* हर वर्ष खप्पर दर्शन के लिए कवर्धा और आसपास के जिलों से हजारों श्रद्धालु पहुंचते हैं। इस वर्ष

भी अपार भीड़ की संभावना है। प्रशासन और पुलिस द्वारा सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रखी जाएगी ताकि श्रद्धालु शांतिपूर्वक दर्शन कर सकें और कोई असुविधा न हो। यातायात और भीड़ प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

आस्था का अनूठा स्वरूप* कवर्धा के ये तीन देवी मंदिर आस्था के प्रमुख केंद्र हैं। अष्टमी की मध्यरात्रि का यह अनुष्ठान भक्तों के लिए विशेष महत्व रखता है। लोग मानते हैं कि इस रात देवी मां साक्षात् नगरवासियों को दर्शन देती हैं। 19 अक्टूबर की मध्यरात्रि को शुरू होने वाली यह खप्पर यात्रा कवर्धा की धार्मिक पहचान और सदियों पुरानी परंपरा का जीवंत प्रमाण बनेगी। दशहरा के अवसर पर शहर में आस्था और उत्साह का माहौल रहेगा।



बासेन में रक्षा गौधाम फउंडेशन का भव्य भंडारा, सेवा और समर्पण की मिसाल बना आयोजन

बलरामपुर (जनता के गोठ) : सेवा, समर्पण और मानवता के संदेश के साथ रक्षा गौधाम फउंडेशन द्वारा रक्षा गौ सेवा आश्रम, बासेन में भव्य भंडारे का आयोजन किया गया। भंडारे में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं एवं क्षेत्रवासियों ने पहुंचकर प्रसाद ग्रहण किया। आयोजन के माध्यम से संस्था ने समाज में सेवा-सहयोग की भावना को मजबूत करने और जनकल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराने का संदेश दिया।

जनसहभागिता से मजबूत हुआ सेवा का संकल्प- रक्षा गौधाम फउंडेशन की ओर से आयोजित इस भंडारे का उद्देश्य धार्मिक आस्था के साथ सामाजिक सद्भाव, आपसी सहयोग और मानवता की भावना को प्रोत्साहित करना रहा। आयोजन में क्षेत्रवासियों की सहभागिता ने सामाजिक कार्यों



में जनसहयोग के महत्व को रेखांकित किया। संस्था ने भंडारे में सहयोग देने वाले श्रद्धालुओं, सेवाभावियों और सहयोगकर्ताओं

के प्रति आभार जताया।

गौसेवा और जनकल्याण के लिए प्रतिबद्ध संस्था- फउंडेशन के पदाधिकारियों के अनुसार,

संस्था समाजसेवा, गौसेवा और जनकल्याण के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। जनसहयोग के माध्यम से जरूरतमंदों की सहायता करना तथा समाज में सेवा और करुणा की भावना को मजबूत बनाना संस्था के प्रमुख उद्देश्यों में शामिल है। संस्था ने भविष्य में भी इसी तरह के सेवा एवं जनकल्याणकारी कार्यों को निरंतर जारी रखने का संकल्प दोहराया।

सेवा को बनाया समाज से जुड़ने का माध्यम- रक्षा गौधाम फउंडेशन का यह आयोजन इस संदेश के साथ संपन्न हुआ कि सामाजिक सहयोग और सामूहिक सहभागिता से सेवा कार्यों को नई मजबूती मिल सकती है। भंडारे जैसे आयोजन धार्मिक आस्था के साथ समाज में परस्पर सहयोग और मानवीय संवेदनाओं को बढ़ावा देने का माध्यम बनते हैं।

जनता के गोठ/ओंकार साहू बलौदाबाजार। नशामुक्त भारत और राष्ट्रीय एकता का संदेश लेकर निकली राष्ट्रव्यापी मोटरसाइकिल रैली का 18 अक्टूबर को सिमगा नगर में भव्य स्वागत किया गया। 'फ़ाइट अगेस्ट ड्रग्स' और 'राष्ट्रीय एकता दिवस-2026' के तहत निकाली गई इस रैली में छत्तीसगढ़ एवं ओडिशा पुलिस के जवान शामिल हैं। रैली का उद्देश्य युवाओं और आम नागरिकों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना तथा राष्ट्रीय एकता का संदेश जन-जन तक पहुंचाना है।

पुलिस अधीक्षक गौरव राय के निर्देशन में रैली के सिमगा पहुंचने पर रायल ढाबा के पास स्वागत कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष आनंद यादव, पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष भागवत सोनकर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक खोमन लाल सिन्हा,



एसडीओपी भाटापारा मयंक रणसिंह तथा थाना प्रभारी सिमगा परिवेश तिवारी सहित अन्य गणमान्य नागरिकों ने रैली में शामिल पुलिस अधिकारियों और जवानों का पुष्पहार पहनाकर आत्मीय स्वागत किया।

इस अवसर पर उपस्थित लोगों को नशे के दुष्प्रभावों से अवागत कराते हुए युवाओं से नशे से दूर रहने की अपील की गई। वक्ताओं ने कहा कि नशा व्यक्ति के स्वास्थ्य,

परिवार और भविष्य को प्रभावित करता है। स्वस्थ युवा और सुरक्षित समाज के निर्माण के लिए नशामुक्ति के प्रति जागरूकता जरूरी है। कार्यक्रम में 'नशे को ना, जिंदगी को हां' का संदेश देते हुए समाज के प्रत्येक नागरिक से इस अभियान में सहभागी बनने का आह्वान किया गया।

स्ट्रेच्यू ऑफयूनिटी की ओर बढ़ा रैली दल- छत्तीसगढ़ और ओडिशा पुलिस के जवानों की

सहभागिता वाली यह मोटरसाइकिल रैली विभिन्न जिलों और राज्यों से होते हुए गुजरात के एकता नगर स्थित स्ट्रेच्यू ऑफ यूनिटी की ओर अग्रसर है। सिमगा में स्वागत एवं जनजागरूकता कार्यक्रम के बाद रैली बेमेतरा जिले के लिए रवाना हुई। इस अभियान के माध्यम से नशामुक्त समाज के निर्माण के साथ देश की एकता, अखंडता और सामाजिक जिम्मेदारी का संदेश दिया जा रहा है।

बकावंड में नवरात्रि पर ग्राम पंचायत ने कराया भंडारा



माता के दर्शन के लिए आने-जाने वाले श्रद्धालुओं को बांटा गया प्रसाद, जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने निभाई सहभागिता

बकावंड जनता के गोठ। बकावंड ब्लॉक मुख्यालय में नवरात्रि के पावन अवसर पर ग्राम पंचायत की ओर से भंडारे का आयोजन किया गया। इस दौरान माता के दर्शन के लिए आने-जाने

वाले श्रद्धालुओं के साथ-साथ रास्ते से गुजरने वाले लोगों को भी प्रसाद वितरित किया गया।

इस धार्मिक आयोजन में श्रद्धालुओं को प्रसाद बांटकर सेवा और धार्मिक आस्था का संदेश दिया गया। भंडारे में सरपंच डमरू मोर्य सहित जगमोहन ठाकुर, विष्णुवर चंद्राकर, कुमारी ठाकुर, भूमि यादव, बसंती ठाकुर, पीताम्बर यादव, जयमनी मोर्य, जया, रीना और मनमती सहित अन्य लोग उपस्थित रहे।

SIR पर विजय शर्मा का कांग्रेस पर तीखा हमला, बोले-कुवैत के मुसलमान का नाम वोटर लिस्ट में कैसे? ऐसे नाम 100 बार कटेंगे!

कवर्धा /जनता के गोठ। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में स्टूड्रू को लेकर सियासत गरमा गई है। मतदाता सूची से 60 हजार से अधिक नाम काटे जाने के विरोध में कांग्रेस जहां रैली निकालकर विरोध जता रही है, वहीं प्रदेश के उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। विजय शर्मा ने पिछली सरकार के कार्यकाल का हवाला देते हुए मतदाता सूची में कथित तौर पर बाहरी लोगों के नाम शामिल होने पर सवाल उठाए। उन्होंने यहां तक कह दिया कि ऐसे लोगों के नाम 100 बार कटेंगे, जिन्हें जो कहना है, कह लें। इतना ही नहीं, उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं को कटे हुए नामों की पूरी जानकारी और पते के साथ कवर्धा शहर में फ्लैक्स लगवाने के निर्देश देने की बात कही और प्रेस कॉन्फ्रेंस कराया , डिटी सीएम के



निर्देश पर जिला पंचायत उपाध्यक्ष और भाजयुमो ने स्थानीय सर्किट हाउस में प्रेसवाता किया वहीं उपमुख्यमंत्री ने इन नामों की सूची कांग्रेस कार्यालय में सौंपने की बात कहकर सियासी पारा चढ़ा दिया है।

SIR यानी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर कवर्धा में राजनीतिक घमासान तेज हो गया है। कांग्रेस मतदाता सूची से बड़ी संख्या में नाम काटे जाने का विरोध कर रही है। इसी मुद्दे पर विजय शर्मा ने कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए सवाल किया कि जब पिछली सरकार के समय कथित

तौर पर बाहरी लोगों के नाम मतदाता सूची में शामिल किए जा रहे थे, तब कांग्रेस को यह सब क्यों नहीं दिखाई दिया? उपमुख्यमंत्री ने कांग्रेस की विरोध रैली पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं से कटे हुए नामों की पूरी जानकारी और पते के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने को कहा है। साथ ही कवर्धा शहर में फ्लैक्स लगाकर इन नामों को सार्वजनिक करने और सूची कांग्रेस कार्यालय में सौंपने की बात कही। गौरतलब है कि जिले में 60 हजार से अधिक नाम काटे जाने का दावा करते हुए कांग्रेस इसका विरोध कर रही है। अब विजय शर्मा के इस बयान के बाद स्टूड्रू को लेकर सियासी टकराव और तेज होने के आसार हैं। हालांकि, इस बयान पर कांग्रेस की ओर से फिलहाल कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

दिव्यांगजन पेंशन के नियमों में संशोधन पर सुमन्त प्रजापति ने जताया प्रधानमंत्री का आभार

80 प्रतिशत की जगह 40 प्रतिशत दिव्यांगता और जन्म से पात्रता की मांग पर संशोधन का दावा; पेंशन राशि पांच हजार रुपये करने सहित तीन प्रमुख मांगें उठाईं

जाह्निक अंसारी सूरजपुर दिव्यांगजनों की पेंशन संबंधी समस्याओं के निराकरण और पात्रता प्रक्रिया को सरल बनाने की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ विकलांग एकता संघ ने वर्ष 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर जापान सौंपा था। अब दिव्यांगजन पेंशन के नियमों में संशोधन की जानकारी सामने आने पर संघ के प्रदेश अध्यक्ष सुमन्त प्रजापति ने प्रधानमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया है। उन्होंने इसे दिव्यांगजनों के अधिकारों और आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में सकारात्मक पहल बताया। हालांकि, उन्होंने पेंशन की राशि बढ़ाकर पांच हजार रुपये प्रतिमाह करने सहित अन्य मांगों को भी प्रमुखता से उभारा है।



दिल्ली में प्रधानमंत्री से मिलकर सौंपा था जापान- सुमन्त प्रजापति के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ विकलांग एकता संघ के प्रतिनिधिमंडल ने वर्ष 2018 में दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। प्रतिनिधिमंडल में संघ की उपाध्यक्ष गिरिजा लखन्यी, कोषाध्यक्ष पुरन राम, सचिव अशोक सिंह आर्याम और सदस्य ठाकुरी राजवाड़े शामिल थे। प्रतिनिधिमंडल ने छत्तीसगढ़ में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 को प्रभावी रूप से लागू करने, पेंशन प्रक्रिया का सरलीकरण करने और पात्रता संबंधी कठिनाइयों को दूर करने की मांग की थी।

जापान में दिव्यांगता प्रमाणपत्र, मेडिकल बोर्ड से जुड़े नियमों तथा पात्र हितग्राहियों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने में आने वाली परेशानियों का निराकरण करने की मांग की गई थी।

पेंशन की राशि पांच हजार रुपये करने की मांग- सुमन्त प्रजापति ने कहा कि दिव्यांगजनों के लिए पात्रता के नियमों में बदलाव स्वागतयोग्य है, लेकिन केवल पात्रता का दावा बढ़ाने से उनकी आर्थिक समस्याओं का समाधान नहीं होगा। वर्तमान महंगाई में भोजन, कपड़े, शिक्षा, स्वास्थ्य, दवाइयों, सहायक उपकरणों और आवागमन का खर्च उठाना दिव्यांगजनों के लिए चुनौतीपूर्ण है। उन्होंने कहा कि पेंशन की राशि इतनी होनी चाहिए कि दिव्यांगजन किसी पर निर्भर हुए बिना सम्मान और आत्मनिर्भरता के साथ जीवन जी सकें। संघ की प्रमुख मांग है कि दिव्यांगजन पेंशन की राशि बढ़ाकर पांच हजार रुपये प्रतिमाह की जाए। साथ ही केंद्र और राज्य सरकारों की वित्तीय जिम्मेदारियां भी स्पष्ट और पारदर्शी होनी चाहिए।



कवर्धा/जनता के गोठ। राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' और 'नशामुक्त भारत, सशक्त भारत' का संदेश जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से ओडिशा से निकाली गई राष्ट्रीय मोटरसाइकिल रैली का 18 अक्टूबर को कबीरधाम जिले के सिमल चौक में भव्य स्वागत किया गया। 'फ़ाइट अगेस्ट ड्रग्स' (नशे के विरुद्ध अभियान) थीम पर आयोजित इस रैली में शामिल

ओडिशा एवं छत्तीसगढ़ पुलिस के बाइक राइडर्स का पुलिस अधिकारियों, युवाओं और नागरिकों ने पुष्पमाला पहनाकर तथा तिलक लगाकर आत्मीय अभिनंदन किया। कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र कुमार यादव, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हेमसागर सिदार, उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय आशीष शुकला, एसडीओपी अजाक/क्राइम प्रशांत देवानग, रक्षित निरीक्षक यातायात महेश



सिंह, सिटी कोतवाली थाना प्रभारी लालजी सिन्हा, उप निरीक्षक अजयकांत तिवारी सहित कबीरधाम पुलिस के अधिकारी-कर्मचारी मौजूद रहे। इस दौरान स्वामी विवेकानंद एकेडमी के युवक-युवतियों और आम नागरिकों ने भी सहभागिता निभाई।

पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र कुमार यादव ने अपने संबोधन में कहा कि नशा व्यक्ति के स्वास्थ्य, परिवार और समाज के भविष्य पर प्रतिकूल

प्रभाव डालता है। विशेषकर युवाओं को नशे से दूर रहकर अपनी ऊर्जा राष्ट्र निर्माण और सकारात्मक गतिविधियों में लगानी चाहिए। उन्होंने नागरिकों से नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूकता फैलाने तथा मादक पदार्थों के अवैध कारोबार की जानकारी पुलिस को देने की अपील की।

उन्होंने कहा कि नशामुक्त समाज के निर्माण के लिए पुलिस के साथ-साथ आम नागरिकों की

सहभागिता भी आवश्यक है। जागरूकता और सामूहिक प्रयासों से ही नशे के खिलाफ प्रभावी लड़ाई लड़ी जा सकती है।

राष्ट्रीय मोटरसाइकिल रैली के माध्यम से कबीरधाम में राष्ट्रीय एकता, सामाजिक समरसता और नशामुक्त भारत का संदेश दिया गया। पुलिस ने युवाओं से नशे से दूर रहने और दूसरों को भी इसके प्रति जागरूक करने का आह्वान किया।

बनसांकरा के बड़े चौरा चौक में श्री संगम दुर्गात्सव की भव्य भूलभुलैया एवं झांकी, चौथे वर्ष भी आकर्षण का केंद्र



विशाल साहू और लोकेश साहू ने अपनी रचनात्मकता व मेहनत से तैयार की आकर्षक भूलभुलैया

जनता के गोठ/ओंकार साहू बलौदाबाजार। सिमागा ब्लॉक अंतर्गत ग्राम बनसांकरा के बड़े चौरा चौक में श्री संगम दुर्गात्सव समिति द्वारा भूलभुलैया एवं झांकी दर्शन का आयोजन लगातार चौथे वर्ष किया जा रहा है। दुर्गात्सव के अवसर पर तैयार की गई आकर्षक भूलभुलैया और मनमोहक झांकी श्रद्धालुओं के लिए खास आकर्षण बनी हुई है। धार्मिक आस्था, रचनात्मकता और उत्साह से सजे इस आयोजन को लेकर क्षेत्र में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है।

इस भव्य भूलभुलैया के मुख्य निर्माणकर्ता विशाल साहू एवं लोकेश साहू हैं। दोनों ने अपनी मेहनत, लगन और

रचनात्मक सोच से भूलभुलैया को आकर्षक स्वरूप प्रदान किया है। भूलभुलैया का निर्माण श्रद्धालुओं को एक अलग अनुभव देने के उद्देश्य से किया गया है, वहीं झांकी के माध्यम से धार्मिक वातावरण को और भी मनमोहक बनाने का प्रयास किया गया है।

श्री संगम दुर्गात्सव समिति द्वारा लगातार चौथे वर्ष इस आयोजन को आगे बढ़ाना धार्मिक परंपरा और सामूहिक सहभागिता का प्रतीक है। ऐसे आयोजन न केवल लोगों की धार्मिक भावनाओं को जोड़ते हैं, बल्कि गांव में उत्सव, आपसी मेल-मिलाप और सामाजिक एकता की भावना को भी मजबूत करते हैं। बड़े चौरा चौक में आयोजित श्री संगम दुर्गात्सव का यह आयोजन श्रद्धालुओं के लिए आस्था और आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। भूलभुलैया एवं झांकी के निर्माण में योगदान देने वाले विशाल साहू और लोकेश साहू की मेहनत आयोजन को विशेष पहचान दे रही है।

भिलाई इस्पात संयंत्र की बिजली का दुष्प्रचार कांग्रेस का सफेद झूठ, हिम्मत है तो तथ्य सामने लाएं: सांसद लक्ष्मी वर्मा

कहा— राजनीतिक हताशा में भ्रम फैला रहे भूपेश बघेल और देवेंद्र यादव, बिना शर्त माफी मांगे कांग्रेस

तरुण बन्धोर- जनता के गोठ

रायपुर। भिलाई इस्पात संयंत्र (BSP) को निजी हाथों अथवा अडानी समूह को बेचे जाने के कांग्रेस के आरोपों पर भारतीय जनता पार्टी ने कड़ा प्रहार किया है। भाजपा की राज्यसभा सांसद लक्ष्मी वर्मा ने इन दावों को पूरी तरह मनगढ़ंत, भ्रामक और सफेद झूठ करार दिया है। उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व को खुली चुनौती देते हुए कहा कि यदि उनके आरोपों में रती भर भी सच्चाई है, तो अनर्गल प्रलाप करने के बजाय वे जनता के सामने इसके ठोस तथ्य और प्रमाण पेश करें, अन्यथा अपने इस गैर-जिम्मेदाराना और झूठे प्रचार के लिए बिना शर्त सार्वजनिक माफी मांगें।

सांसद लक्ष्मी वर्मा ने कहा कि भिलाई स्टील प्लांट महज एक



औद्योगिक उपक्रम नहीं, बल्कि भिलाई सहित समूचे छत्तीसगढ़ के मान-सम्मान, अस्मिता और लाखों कर्मठ श्रमिकों के पसीने की पहचान है। जब भी कांग्रेस राजनीतिक रूप से अपरासंगिक होती है, वह जनता के बीच भय, भ्रम और अविश्वास का वातावरण तैयार करने की साजिश रचने लगती है। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और विधायक देवेंद्र यादव पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि जनाधार खो चुके ये नेता गहरी हताशा और कूटु में धिरकर राज्य के गौरव से जुड़े उपक्रम को लेकर खुलेआम अपह्वाहें फैलाने का निंदनीय काम

कर रहे हैं।

श्रीमती वर्मा ने स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार भिलाई इस्पात संयंत्र के आधुनिकीकरण, क्षमता विस्तार और इसे नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए निरंतर संकल्पित होकर काम कर रही है। संयंत्र को सशक्त बनाना सरकार की प्राथमिकता है, जबकि कांग्रेस केवल धार्तिया फैलाकर श्रमिकों और प्रदेशवासियों को दिग्भ्रमित करना चाहती है।

कांग्रेस के पिछले कार्यकाल को घेरते हुए भाजपा सांसद ने कहा कि अपने शासनकाल में भ्रष्टाचार और घोटालों के कीर्तिमान स्थापित करने वाली कांग्रेस के पास आज जनहित का कोई मुद्दा नहीं बचा है। सनसनी फैलाकर अपना राजनीतिक अस्तित्व बचाने के लिए कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व झूठ की फैक्ट्री संचालित कर रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ की प्रबुद्ध जनता उनके इस कपटपूर्ण और नकारात्मक एजेंडे को भली-भांति समझ चुकी है।

जंगल उजाड़ने और नदियां जहरीली करने से बढ़ा मानव-वन्यजीव संघर्ष, भाजपा की नीतियां जिम्मेदार: कांग्रेस

प्रदेश प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा का आरोप— कॉरपोरेट मित्रों के लाभ के लिए सिमट रहे वन क्षेत्र, एक हफ्ते में आधा दर्जन से ज्यादा मौतें

तरुण बन्धोर- जनता के गोठ

रायपुर। छत्तीसगढ़ में मानव और वन्यजीवों के बीच बढ़ते संघर्ष को लेकर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने राज्य की भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। प्रदेश कांग्रेस कमिटी के मुख्य प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा कि छत्तीसगढ़ आज एक भीषण पर्यावरणीय और मानवीय त्रासदी के मुहाने पर खड़ा है। सरकार की अदृढ़दर्शी और कॉरपोरेट परस्त नीतियों, अंधाधुंध अवैध खनन तथा औद्योगिक कचरे के कारण प्रदेश के जंगल सिकुड़ रहे हैं और नदियां प्रदूषित हो रही हैं। इसी का नतीजा है कि जंगली जानवर बस्तियों की ओर रुख कर रहे हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार जान-माल का नुकसान हो

रहा है।

एक सप्ताह में आधा दर्जन से अधिक मौतें, कई घायल

हालिया घटनाओं का हवाला देते हुए सुरेंद्र वर्मा ने बताया कि बीते केवल एक हफ्ते में आधा दर्जन से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है।

- धमतरी व कोंडगांव सीमा: बोर्ड और कारीपानी क्षेत्र में तेंदुए के हमले से एक गर्भवती महिला समेत दो लोगों की मौत हो गई, जबकि 16 लोग घायल हुए।

- महासमुंद: बागबाहरा वन क्षेत्र के झिटकी गांव में रात के वक घर में घुसे तेंदुए ने 4 महिलाओं और 2 पुरुषों समेत 6 लोगों को घायल कर दिया।

- कांकर: माकड़ी सिंगराय इलाके में भालू के हमले में एक महिला गंभीर रूप से जख्मी हो गई। - जशपुर: तपकरा वन परिक्षेत्र में दंतैल हाथियों को खदेड़ने के दौरान कुचलने से एक नाबालिग की जान चली गई।

उन्होंने आरोप लगाया कि



प्रशासनिक विफलता और सरकार की लापरवाही के कारण आदिवासी और ग्रामीण अपनी जान गंवा रहे हैं, वहीं वन्य प्राणी भी तड़प-तड़प कर मरने को विवश हैं।

कांरपोरेट हितों के लिए जंगलों की कटाई और नदियों में बहाया जा रहा अपशिष्ट

कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि सरकार हरियाली और वन सुरक्षा के दावे तो करती है, लेकिन जमीनी हकीकत इसके उलट है। कॉरपोरेट उद्योगों को लाभ पहुंचाने के लिए जंगलों की कटाई, अंधाधुंध खनन और संसाधनों का अस्तंत्तित दोहन जारी है। हाथियों के आवागमन गलियारों (कांरिडोर) और प्रस्तावित एलिफेंट रिजर्व के फंड और सुरक्षा तंत्र में भारी अनदेखी की जा रही है। इसके साथ ही शिवनाथ, हसदेव, खारन, महानदी, अरपा, शबरी, गंडकी और इंद्रावती जैसी जीवनदायिनी नदियों में बिना ट्रीटमेंट के सीधे औद्योगिक अपशिष्ट बहाया जा रहा है। हसदेव सहित अन्य वन क्षेत्रों में पेड़ों की कटाई पर सरकार मूकदर्शक बनी हुई है, जिससे सरगुजा, रायगढ़, कोरबा और बस्तर के ग्रामीण खोफ में राते बिता रहे हैं।

पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के प्रयासों को ठप करने का आरोप सुरेंद्र वर्मा ने कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस शासनकाल में मानव-वन्यजीव संघर्ष को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए गए थे। 'लेमरू एलिफेंट रिजर्व' को धरातल पर उतारा गया, हाथियों की निगरानी के लिए रेडियो कॉलरिंग और एआई (ट्र) आधारित ट्रैकिंग सिस्टम लागू किया गया। इसके अलावा 'नरवा जारी है। हाथियों के आवागमन अंदर नालों का जीर्णोद्धार किया गया, ताकि वन्यजीवों को जंगल के भीतर ही पर्याप्त भोजन और पानी मिल सके और वे इंसानी बस्तियों की ओर न आए। भाजपा की सरकार आते ही ये सभी जनहितकारी योजनाएं ठप कर दी गईं।

उन्होंने कहा कि जंगलों के कटने से तेंदुए, महुआ और लघु वनोपज संग्रहकों की आजीविका पर भी गहरा संकट खड़ा हो गया है। सरकार विकास के नाम पर आदिवासियों के जल, जंगल और जमीन की अनदेखी कर रही है, जिसके चलते पिछले पौने तीन वर्षों में दोनों तरफ से मौतों का आंकड़ा निरंतर बढ़ रहा है।

बजाज फ़र्नस की ओर से एलन इंस्टीट्यूट रायपुर में साइबर जागरूकता अभियान आयोजित

रायपुर। डिजिटल युग में बढ़ते साइबर अपराधों और ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी के प्रति विद्यार्थियों को जागरूक करने के उद्देश्य से बजाज फ़र्नस की ओर से रायपुर स्थित एलन इंस्टीट्यूट में साइबर जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। इस अभियान के माध्यम से विद्यार्थियों को साइबर अपराधों के विभिन्न तरीकों, ऑनलाइन ठगी से बचाव तथा डिजिटल लेनदेन के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में एसपी कोतवाली श्री दीपक मिश्रा विशेष रूप से उपस्थित रहे। साइबर पुलिस के अधिकारी श्री महेंद्र सिंह राजपूत एवं श्री अमित वर्मा ने विद्यार्थियों को साइबर सुरक्षा के महत्वपूर्ण पहलुओं से अवगत कराया। अधिकारियों ने बताया कि इंटरनेट, सोशल मीडिया, ऑनलाइन बैंकिंग और डिजिटल भुगतान के बढ़ते उपयोग के साथ साइबर अपराधी भी ठगी के नए-नए तरीके अपना रहे हैं। ऐसे में जागरूकता और सतर्कता बेहद आवश्यक है। अभियान के दौरान विद्यार्थियों को फर्नी फेन कॉल, सदिग्ध लिंक, फर्जी मैसेज, सोशल मीडिया के माध्यम से होने वाली धोखाधड़ी, ऑनलाइन भुगतान में ठगी तथा बैंकिंग संबंधी गोपनीय जानकारी हासिल कर किए जाने वाले साइबर अपराधों के बारे में जानकारी दी गई। साइबर पुलिस के अधिकारियों ने डिजिटल अस्प्रेट के नाम पर की जाने वाली ठगी के प्रति भी सतर्क रहने की अपील की। उन्होंने विद्यार्थियों को साइबर अपराध की स्थिति में उचित माध्यम से शिकायत दर्ज कराने तथा समय रहते पुलिस की सहायता लेने के लिए प्रेरित किया। इस अभियान में बजाज फ़र्नस रायपुर शाखा की ओर से रीजनल मैनेजर श्री पंकज गायकवाड़, सीनियर एरिया मैनेजर श्री मनीष उके एवं एरिया मैनेजर श्री निखिल मिश्रा ने सहभागिता की। कार्यक्रम के माध्यम से विद्यार्थियों को यह संदेश दिया गया कि साइबर सुरक्षा प्रत्येक इंटरनेट उपयोगकर्ता की

57 हजार शिक्षक भर्ती के वादे के बीच घटे 2582 शिक्षक, यू-डायस रिपोर्ट से खुला साय सरकार का सच: दीपक बैज

तरुण बन्धोर- जनता के गोठ

रायपुर। छत्तीसगढ़ में शिक्षकों की भर्ती और सरकारी स्कूलों की स्थिति को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। प्रदेश कांग्रेस कमिटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने राज्य की विष्णुदेव साय सरकार पर डीएड, बीएड और टीईटी पास बेरोजगार युवाओं के भविष्य के साथ बड़ा छल करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने सत्ता में आने से पहले 57 हजार शिक्षकों की भर्ती का जोर-शोर से प्रचार किया था, लेकिन हकीकत यह है कि केंद्र सरकार की ही 'यू-डायस प्लन' (UDISE+) रिपोर्ट ने सरकार के दावों की पोत खोल दी है। राज्य में शिक्षकों के पद भरने के बजाय उल्टे 2,582 शिक्षक कम हो गए हैं।

दो वर्षों में 2,582 शिक्षक घटे, यू-डायस के आंकड़ों का दिया हवाला- प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने केंद्र सरकार की यू-डायस प्लन रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि वर्ष 2023-24 में छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में कुल शिक्षकों की संख्या 1,88,721 थी, जो 2024-25 में घटकर 1,88,578 और 2025-26 में और कम होकर 1,86,139 पर आ गई। इस प्रकार पिछले दो वर्षों में राज्य के सरकारी स्कूलों में 2,582 शिक्षक कम हो गए। दीपक बैज ने कहा कि यह रिपोर्ट स्पष्ट करती है कि साय सरकार रोजगार देने वाली नहीं, बल्कि युवाओं से रोजगार छीनने वाली सरकार साबित हुई है।

एकल-शिक्षक स्कूलों की संख्या बढ़ी, आदिवासी व ग्रामीण अंचल प्रभावित- दीपक बैज ने कहा कि प्रदेश में एकल-शिक्षक और शिक्षक-विहीन स्कूलों की संख्या लगातार बढ़ रही है। भर्ती के नाम पर केवल कमेटीय गठित की जा रही हैं और बेरोजगारों को बयानों का झुनझुन थमाया जा रहा



है, जबकि बजट में वित्तीय प्रावधानों की कटौती की जा रही है। उन्होंने कहा कि बस्तर, सरगुजा और मैदानी इलाकों के सरकारी स्कूलों में विषय-विशेषज्ञ शिक्षकों के न होने से शिक्षा की गुणवत्ता गिर रही है। यह सीधे तौर पर गरीब और आदिवासी बच्चों को अच्छी शिक्षा से वंचित करने की साजिश है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या सरकारी शिक्षा तंत्र को जानबूझकर कमजोर किया जा रहा है ताकि निजी शिक्षा माफियाओं को लाभ पहुंचाया जा सके?

पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कार्यों से की तुलना- पूर्ववर्ती भूपेश बघेल सरकार के कामकाज का उल्लेख करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस के कार्यकाल में शिक्षा व्यवस्था को प्राथमिकता दी गई थी। स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी व हिंदी माध्यम योजना के तहत 20,000 से अधिक पद स्वीकृत कर नियुक्तियां की गईं और 27,069 नियमित शिक्षक भर्ती (14,580 एवं 12,489 पद) की शर्कल रही है। लाखों प्रशिक्षित युवा वर्षों से कोचिंग और तैयारी कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनके सपनों पर पानी फेर रही है।

तरुण बन्धोर- जनता के गोठ

रायपुर। राजधानी के पंडरी क्षेत्र में मासूम बच्चों के साथ अमानवीय मारपीट के मामले पर छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने कड़ा रुख अपनाया है। आयोग की अध्यक्ष डॉ. वर्णिका शर्मा ने स्पष्ट किया है कि बच्चों की सुरक्षा के साथ किसी भी सूरत में समझौता नहीं किया जाएगा। मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बच्चों की माता और सौतेले पिता के खिलाफ प्रार्थमिकी (FIR) दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

मेकाहारा में भर्ती 3 साल के बच्चे का हाल जानने पहुंचीं अध्यक्ष- जानकारी के अनुसार, 15 अक्टूबर को चाइल्ड हेल्पलाइन के माध्यम से पंडरी इलाके में बच्चों पर हो रहे अत्याचार की सूचना मिली



थी। जांच में सामने आया कि 3 वर्षीय और 8 वर्षीय बालकों के साथ बेरहमी से मारपीट की गई थी। गंभीर चोटें आने के कारण 3 साल के मासूम को 16 अक्टूबर को मेकाहारा अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां फ्लिहाल उसका स्वास्थ्य स्थिर बताया गया है। वहीं, 8 वर्षीय बालक को बाल गृह और 6 वर्षीय

बालिका को सुरक्षित संरक्षण के लिए 'मातृछाया' भेजा गया है।

आयोग की अध्यक्ष डॉ. वर्णिका शर्मा ने मे क ा ह ा र ा अ र प त ा ल प ह ँ च क र उपचाराधीन बच्चे

के स्वास्थ्य की जानकारी ली और चिकित्सकों को समुचित उपचार के निर्देश दिए। इसके बाद उन्होंने बाल गृह का दौरा कर दूसरे बालक की सुरक्षा एवं देखभाल की स्थिति का जायजा लिया। डॉ. शर्मा ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि त्यों बच्चों को जरूरी मानसिक और भावनात्मक संबल देने के लिए

नियमित काउंसलिंग कराई जाए और उनके पुनर्वास की पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

चाइल्ड हेल्पलाइन की सक्रियता से समय पर मिला न्याय- डॉ. शर्मा ने बताया कि प्रदेश के थानों और प्रमुख संस्थानों में चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर प्रदर्शित करने की मुहिम के सार्थक परिणाम सामने आ रहे हैं। इसी पहल की वजह से समय रहते बच्चों पर हो रही हिंसा की जानकारी मिली और त्वरित रेस्क्यू संभव हो सका।

उन्होंने चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम की संवेदनशीलता और मुस्तेदी की सराहना करते हुए कहा कि आयोग बच्चों के अधिकारों की रक्षा और उनके विरुद्ध होने वाले हर प्रकार के शोषण को रोकने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

बढ़े बिजली बिल के साथ कोयला सेस जनता पर खुला अत्याचार, 31 प्रतिशत से अधिक बढ़ाई गई दरें: कांग्रेस

प्रदेश प्रवक्ता वंदना राजपूत का आरोप— राशन से ज्यादा आ रहा बिजली बिल, विभाग को बना दिया जबरिया वसूली का केंद्र

तरुण बन्धोर- जनता के गोठ रायपुर। छत्तीसगढ़ में बिजली की दरों में लगातार हो रही वृद्धि और ईंधन प्रभार के नाम पर अतिरिक्त सेस वसूली को लेकर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने राज्य की भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। प्रदेश कांग्रेस कमिटी की मुख्य प्रवक्ता वंदना राजपूत ने आरोप लगाया कि सरकार ने पहले बिजली की दरों में भारी इजाफ

किया और अब उपभोक्ताओं की जेब पर कोयला सेस के जरिए डाका डाल रही है। ईंधन प्रभार के रूप में हर उपभोक्ता से 300 से 1,000 रुपये तक अतिरिक्त वसूले जा रहे हैं, जो सीधे तौर पर जनता के साथ खुली लूट और अत्याचार है।

अंतिम तारीख से पहले ही काटे जा रहे कनेक्शन, वसूली से उपभोक्ता परेशान प्रदेश प्रवक्ता वंदना राजपूत ने कहा कि भाजपा के शासन में विद्युत विभाग को जबरिया वसूली का केंद्र बना दिया गया है। हालात यह हैं कि अक्टूबर माह में बिल भुगतान की अंतिम तारीख (ड्यू डेट) आने से पहले ही पुराना



बकाया बताकर उपभोक्ताओं के

बिजली कनेक्शन काटे जा रहे हैं। कभी अनुबंध भार (सेक्शंड लोड) से अधिक खपत का बहाना बनाकर जुर्माना थोपा जा रहा है, तो कभी सेस और कोयले का अतिरिक्त प्रभार जोड़ दिया जाता है। इस मनमानी वसूली के चलते प्रदेश का आम नागरिक भारी मानसिक व आर्थिक तनाव से जूझ रहा है।

भाजपा सरकार में 5वीं बार बढ़ी दरें, 31.23 प्रतिशत तक की भारी वृद्धि आंकड़ों का हवाला देते हुए वंदना राजपूत ने बताया कि भाजपा के सत्ता में आने के बाद से अब तक 5 बार बिजली के दाम बढ़ाए जा चुके हैं। चालू वर्ष के जुलाई माह

से ही घरेलू बिजली की दरों में 30 से 50 पैसे, गैर-घरेलू में 20 से 40 पैसे और कृषि पंपों की दरों में 40 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की गई। इसके अतिरिक्त 12 प्रतिशत विद्युत ईंधन अधिभार भी थोपा दिया गया। कुल मिलाकर भाजपा सरकार के कार्यकाल में अब तक बिजली की दरों में 31.23 प्रतिशत की बेतहाशा वृद्धि हो चुकी है। इसकी तुलना में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने अपने 5 वर्षों के कार्यकाल में महज 2 पैसे की बढ़ोतरी की थी और 400 यूनिट तक बिजली बिल हाफ योजना के तहत 'बिजली बिल हाफ' योजना का सीधा लाभ भी जनता को दिया था।

राशन के खर्च से ज्यादा बिजली

का बिल, 'बिजली बिल हाफ योजना बंद करने का आरोप कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि आज मध्यम और गरीब वर्ग के परिवारों का मासिक बिजली बिल उनके राशन के खर्च से भी ज्यादा आ रहा है। स्मार्ट मीटरों के कारण तेज रीडिंग और गड़बड़ी की शिकायतें आम हो चुकी हैं। वहीं दूसरी ओर 400 यूनिट तक मिलने वाली बिजली बिल हाफ योजना को बंद कर सरकार ने आम जनता पर दोहरी मार की है। उन्होंने कहा कि सरकार की यह दलील पूरी तरह भ्रामक है कि बिजली सस्ती हुई है; जमीनी हकीकत यह है कि सरकार जनहित और महंगाई के प्रति पूरी तरह संवेदनहीन बनी हुई है।